09
अध्याय

सेवा क्षेत्र

सेवा क्षेत्र आज भी भारत के आर्थिक विकास का मुख्य संचालक है और इस क्षेत्र ने 2016-17 में देश के सकल मूल्य वर्धन की वृद्धि के लगभग 62 प्रतिशत का योगदान किया। लेकिन इस क्षेत्र का विकास पूर्ववर्ती वर्ष में हासिल 9.7 प्रतिशत की तुलना में कम होकर 2016-17 में 7.7 प्रतिशत के स्तर पर आ गया, हालांकि यह कृषि और उद्योग के अन्य दो क्षेत्रों के मुकाबले अधिक बनी हुई है और 15 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में लगभग शीर्ष स्तर पर भी है। संकट के बाद की अवधि में सेवा-निर्यातों की वृद्धि में तेजी से गिरावट हुई, यहां तक कि 2016-17 में धीमी सी वृद्धि के साथ सकारात्मक परिधि में लौटने से पूर्व ये 2015-16 में नकारात्मक भी हो गई थी। सरकार ने विभिन्न सेवाओं के लिए अनेक योजनाएं शुरू की है जैसेकि डिजिटलीकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है तथा पर्यटन और पोत-परिवहन संबंधी नीतियां। इन उपायों के साथ-साथ जीएसटी और एफडीआई उदारीकरण ने इस क्षेत्र के लिए विकास की संभावनाओं को उज्ज्वल बनाया है।

अंतरराष्ट्रीय तुलना

वैश्विक सेवा जीवीए

9.1 वर्ष 2015 में, समग्र जीडीपी के अनुसार विश्व की शीर्ष 15 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ। यह 2014 में 9वें स्थान से 2015 में 7वें स्थान पर पहुंच गई। तथापि, सेवा सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) के अनुसार, भारत की स्थिति को नुकसान हुआ। यह 2014 में 10वें स्थान से गिरकर 2015 में 13वें स्थान पर आ गई। समग्र जीडीपी और सेवा जीवीए दोनों के अनुसार, यूएसए का स्थान प्रथम रहा, जबकि चीन का स्थान दूसरा और छठा है। 2015 में वैश्विक सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) 70.6 ट्रिलियन अमरीकी डालर रहा। सेवा के भाग में (चालू मूल्यों पर) आंशिक सुधाार हुआ। वर्ष 2014 में 66.2 प्रतिशत की तुलना में, यह बढ़कर 67.2 प्रतिशत हो गया। यद्यपि, यह 2001 में हासिल किए गए 68.8 प्रतिशत के मुकाबले अभी भी कम है।

9.2 इन शीर्ष 15 राष्ट्रों में, 2001-15 की अवधि में, जीवीए के मुकाबले सेवा भाग में उच्चतम वृद्धि चीन (8.9 पीपी) द्वारा दर्ज की गई थी, जिसके पश्चात स्पेन (8.1 पीपी), भारत (7.6 पीपी) और रूस (7.6 पीपी) का स्थान था। परंतु, 2010-15 की अवधि के दौरान, भारत ने 8.5 प्रतिशत की दर से उच्चतम चक्रवर्धी वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) हासिल की थी, जिसके बाद 8.4 प्रतिशत की दर से चीन का स्थान था। 2014 की तरह 2015 में, विश्व के लिए सेवा जीवीए वृद्धि दर (स्थिर मूल्यों पर) 2.6 प्रतिशत थी, जबकि भारत के लिए यह दर 2014 और 2015 दोनों में क्रमशः 10.2 प्रतिशत और 9.0 प्रतिशत की दर से उच्चतम थी, इसके बाद चीन का स्थान था, जिसकी इन्हीं वर्षों के लिए यह दर क्रमशः 7.9 प्रतिशत और 8.3 प्रतिशत थी (सारणी 1)।

9.3 कुछ देशों के उपलब्ध नवीनतम जीडीपी आकलनों से पता चलता है कि सेवा क्षेत्र में वृद्धि सामान्य रही। संयुक्त राज्य अमरीका में, सेवा क्षेत्र की वृद्धि 2015 में 2.8 प्रतिशत से घटकर 2016 में 1.9 प्रतिशत रह गई जिसका मुख्य कारण रियल एस्टेट, पेशेवर और व्यावसायिक सेवाओं जैसे क्षेत्रों में गिरावट थी। चीन में

सारणी 1. सेवा क्षेत्र का निष्पादनः अंतरराष्ट्रीय तुलना

देश	रैंक		सेवा वृद्धि दर			सेवाओं का हिस्सा			सेवा निर्यात वृद्धि			
	समग्र जीडीपी	सेवा जीवीए	(प्रतिशत) वर्षानुवर्ष		सीएजीआर 2010-15	जीवीए	रोजगार	कुल निर्यात	(प्रतिशत) वर्षानुवर्ष		सीएजीआर 2001-08	सीएजीआर 2010-16
			2001	2015		2015	2016*	2016	2001	2016		
यूएसए	1	1	2.0	2.8	1.6	79.3	80.0	33.5	-3.6	0.3	9.5	5.1
चीन	2	6	10.3	8.3	8.4	49.7	42.4	9.0	9.1	-4.3	23.6	2.6
यूके	5	4	3.4	2.4	2.2	79.9	80.0	44.6	-0.8	-4.9	14.5	3.3
भारत	7	13	7.2	9.0	8.5	53.2	28.6	37.9	4.8	3.6	30.0	5.6
ब्राजील	9	10	2.2	-2.7	1.3	72.0	68.9	14.9	-2.7	-1.3	18.6	1.8
द. कोरिया	11	12	4.9	2.9	3.0	59.7	70.2	15.6	-4.9	-5.0	17.4	1.8
मैक्सिको	15	9	1.1	3.6	3.4	60.4	61.2	6.1	-7.5	5.3	5.3	7.9
विश्व			**2.6**	**2.6**	**2.4**	**67.2**	**50.9**	**23.0**	**0.1**	**0.4**	**14.9**	**3.8**

स्रोतः **जीडीपी/जीवीए के लिए यूएन नेशनल एकाउंट्स स्टेटिस्टिक्स, रोजगार के लिए विश्व बैंक डाटाबेस तथा सेवा व्यवसाय के लिए विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) डाटाबेस से संगणित।**

टिप्पणीः **रैंक और हिस्सा चालू मूल्यों (2015) पर आधारित हैं; वृद्धि दरें सतत मूल्यों (यूएस डालर) पर आधारित हैं; निर्माण क्षेत्र सेवा जीडीपी में शामिल नहीं हैं; *चीन, भारत और विश्व के लिए 2016 में रोजगार आंकड़ों के लिए निकटतम पिछले वर्ष के उपलब्ध आंकड़े प्रयोग किए गए हैं।**

भी, सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर में मामूली गिरावट आई। यह 2015 में 8.3 प्रतिशत से गिरकर 2016 में 7.8 प्रतिशत पर आ गई। भारत में, सामान्य रुझान के अनुसरण में, सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर 2015-16 में 9.7 प्रतिशत से घटकर 2016-17 में 7.7 प्रतिशत रह गई, यह चीन की तुलना में भले ही थोड़ी कम हो, परंतु अन्य देशों के मुकाबले अभी भी उच्च है।

वैश्विक सेवा रोजगार

9.4 सेवा प्रदान करने वाले शीर्ष 15 देशों में, रोजगार में सेवा क्षेत्र का हिस्सा अधिकतर देशों में 2016 में कुल रोजगार के दो-तिहाई से अधिक बैठता है, जबकि भारत, चीन और मैक्सिको में यह हिस्सेदारी कम है। इसमें भारत का 28.6 प्रतिशत का हिस्सा सबसे कम है। इन 15 देशों में से, 2001 से 2006 के बीच विगत 15 वर्ष की अवधि में, चीन में सेवा रोजगार के हिस्से (14.7 पीपी) में सबसे अधिक वृद्धि हुई थी, जबकि भारत में यह वृद्धि केवल 4.6 पीपी थी (सारणी 1)।

वैश्विक सेवा व्यापार

9.5 वैश्विक वाणिज्यिक सेवा निर्यात की सीएजीआर संकट-पूर्व अवधि (2001-2008) के दौरान हासिल की गई 14.9 प्रतिशत की तुलना में संकट-पश्च अवधि (2010-16) के दौरान घटकर 3.8 प्रतिशत पर आ गई। संकट-पूर्व अवधि में, सेवा प्रदान करने वाले शीर्ष 15 देशों में, भारत की सेवा निर्यात सीएजीआर सबसे तेज 30 प्रतिशत थी, जिसके बाद 26 प्रतिशत के साथ रूस और 23.6 प्रतिशत के साथ चीन का स्थान था। तथापि, संकट-पश्च अवधि (2010-2016) के दौरान, सभी अर्थव्यवस्थाओं में सेवा निर्यात सीएजीआर में गिरावट आई। सबसे अधिक वृद्धि मैक्सिको में 7.9 प्रतिशत दर्ज की गई, जिसके बाद भारत में यह 5.6 प्रतिशत रही। चीन 2.6 प्रतिशत के साथ काफी दूर, 8वें स्थान पर, था। 2015 में, जबकि वैश्विक व्यापार निर्यात (ईंधन को मिलाकर और छोड़कर दोनों), वैश्विक सेवा निर्यात में वृद्धि हुई थी, भारत का वस्तु निर्यात (ईंधन को मिलाकर और छोड़कर दोनों) और भारत का सेवा निर्यात सभी नकारात्मक श्रेणी में थे, वैश्विक सेवा निर्यात के मामले में -5.7 नकारात्मक वृद्धि की तुलना में भारत के सेवा निर्यात के मामले में -0.6 प्रतिशत वृद्धि के साथ यह केवल मामूली रूप से नकारात्मक था (चित्र 1क)।

तथापि, वर्षों बाद भारत के सेवा निर्यात में अधिक गिरावट आई है। समयावधि को दो भागों–संकट-पूर्व और संकट-पश्च में विभाजित कर देने पर यह सामने आता है कि भारत के और विश्व के सेवा निर्यातों में वृद्धि रुझान में संकट-पूर्व अवधि में ज्यादा उतार-चढ़ाव नहीं थे, जबकि संकट के बाद की अवधि में भारत के सेवा निर्यातों में वृद्धि रुझान में गिरावट वैश्विक सेवा निर्यात वृद्धि के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से आई थी (चित्र 1 ख)। यह गिरावट सामान्य वैश्विक माहौल के कारण थी, जिसमें 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट भी शामिल था, 2010 में भारत के सेवा निर्यातों की धीमी पुनर्बहाली जारी न रह सकी, जिसका कारण आगामी वर्षों में कम्प्यूटर और वित्तीय सेवाओं जैसी मुख्य सेवाओं में निर्यातों की धीमी और नकारात्मक वृद्धि थी।

9.6 वर्ष 2016 के लिए विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, अनेक अर्थव्यवस्थाओं के लिए सेवा निर्यात वृद्धि नकारात्मक श्रेणी में है, यद्यपि भारत के लिए 3.6 प्रतिशत पर यह सकारात्मक है और 0.4 प्रतिशत की वैश्विक सेवा निर्यात वृद्धि की तुलना में उच्च है। जहां जापान, आस्ट्रेलिया, स्पेन और मैक्सिको जैसे देशों के लिए भी यह सकारात्मक और भारत से उच्च है, वहीं चीन के लिए यह -4.3 प्रतिशत के साथ नकारात्मक है।

चित्र 1क. व्यापार (ईंधन-भिन्न) और सेवा निर्यातों में वृद्धि: विश्व और भारत (प्रतिशत)

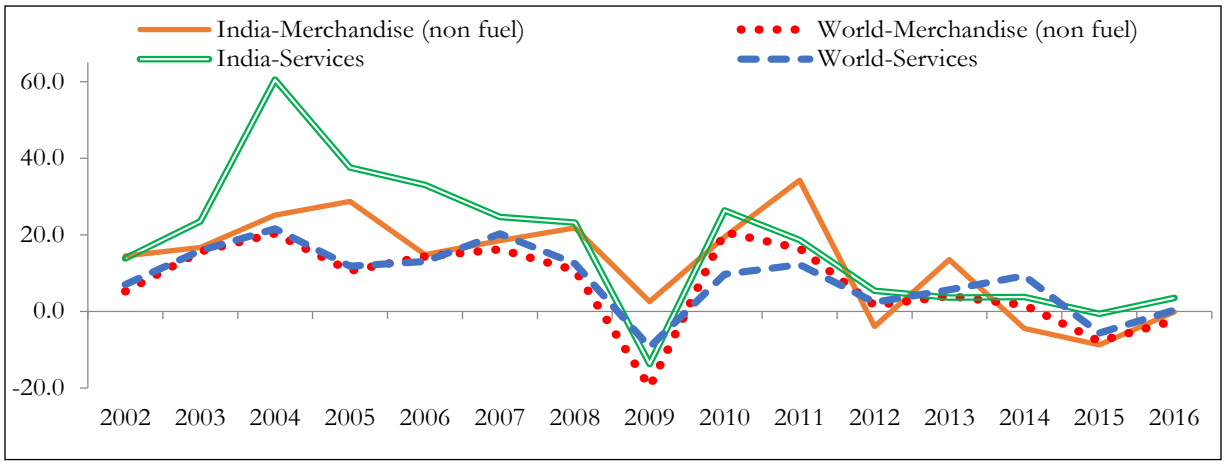

स्रोत: आईटीसी ट्रेड मैप और डब्ल्यूटीओ डाटा पर आधारित

चित्र 1ख. विश्व और भारत में सेवा निर्यात वृद्धि दर: 2009 से पूर्व और पश्च की तुलना (प्रतिशत)

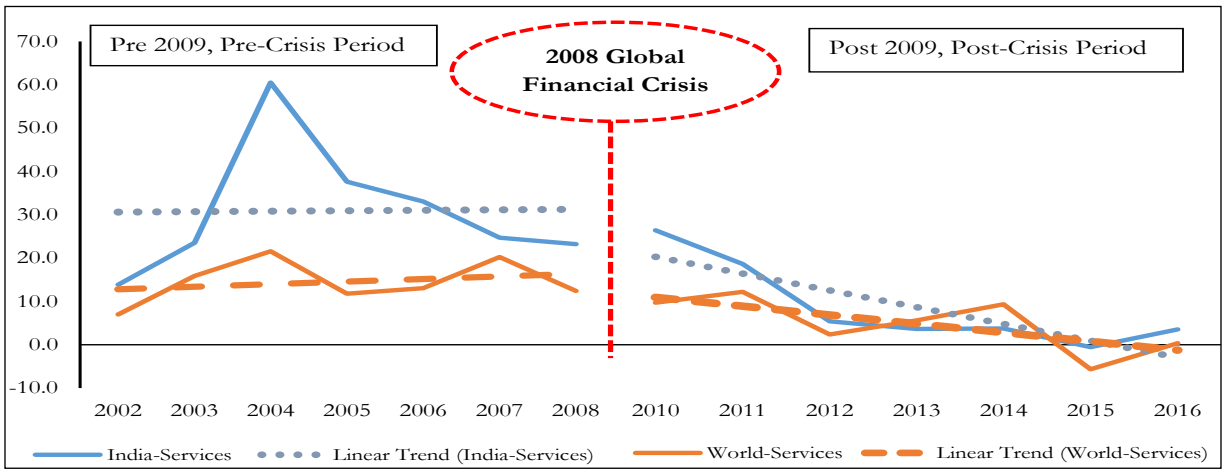

स्रोत: डब्ल्यूटीओ डाटा पर आधारित

वैश्विक सेवा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

9.7 2015 में सेवा क्षेत्र, वैश्विक एफडीआई स्टॉक का 65 प्रतिशत बैठता था, यद्यपि इसका एक बड़ा भाग प्राथमिक क्षेत्र और विनिर्माण एमएनई से सहबद्ध ऐसी संस्थाओं से संबंधित है, जो सेवाओं जैसे कार्यकलापों का निष्पादन करती हैं और किसी पूर्वनिर्धारित (डिफाल्ट) श्रेणी के रूप में सेवा के अंतर्गत आती हैं, इस प्रकार सेवा में बढ़ा-चढ़ा कर बताई गई एफडीआई एक-तिहाई से अधिक है (वर्ल्ड इंवेस्टमेंट रिपोर्ट 2017)। इस रिपोर्ट के अनुसार, 2017-19 में वैश्विक एफडीआई कार्यकलापों के लिए अधिशासियों के अनुमान दर्शाते हैं कि 65 प्रतिशत प्रतिक्रियादाताओं को सेवा में वृद्धि होने की आशा है। बढ़ते डिजिटाइजेशन से, सेवा में अधिक निवेश होने की उम्मीद है। आवक निवेश के समग्र क्षेत्रीय पैटर्न विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में समरूप हैं, परंतु सेवा एफडीआई में विकासशील एशिया सेवाओं का काफी अधिक हिस्सा होने के चलते विकासशील क्षेत्रों में इस पैटर्न संबंधी विभिन्नताएं हैं, जिसका मुख्य कारण यह है कि हांगकांग में सबसे अधिक निवेश हुआ है (वर्ल्ड इंवेस्टमेंट रिपोर्ट 2016)।

9.8 यूनाइटेड नेशन्स कान्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवेल्पमेंट (यूएनसीटीएडी) के ग्लोबल इंवेस्टमेंट ट्रेंड मॉनीटर, फरवरी 2017 अंक के अनुसार, 2016 में वैश्विक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) प्रवाह 1.52 ट्रिलियन अमरीकी डालर के अनुमानित स्तर पर पहुंच कर 13 प्रतिशत कम हो गए क्योंकि वैश्विक आर्थिक विकास कमजोर रहा और विश्व व्यापार में भी कुछ खास उछाल नहीं आया। इस रुझान के अनुरूप, सेवा में वैश्विक एफडीआई में कमी होने की संभावना है।

भारत का सेवा क्षेत्र

सेवा जीवीए और सकल पूंजी निर्माण

9.9 वर्ष 2016-17 के लिए केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) द्वारा जारी किए गए वास्तविक सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) के अनंतिम अनुमानों (पीई) के अनुसार सेवा क्षेत्र वृद्धि (अर्थात् स्थिर (2011-12) मूल कीमतों पर जीवीए) पिछले दो वर्षों में 9.7 प्रतिशत से गिरकर 7.7 प्रतिशत रह गया है, जिसका मुख्य कारण दो सेवा श्रेणियों-व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण संबंधी सेवाओं (7.8 प्रतिशत) तथा वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाओं (5.7 प्रतिशत) में वृद्धि में कमी आना है। तथापि, लोक प्रशासन और अन्य सेवा श्रेणी में वृद्धि दर पिछले वर्ष में 6.9 प्रतिशत से बढ़कर 11.3 प्रतिशत हो गई है, जिसका मुख्य कारण 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन है। चालू कीमतों पर, पिछले कुल सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ) में सेवा क्षेत्र का हिस्सा पिछले चार वर्षों से लगातार बढ़ा है। यह 2011-12 में 53.3 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में 60.3 प्रतिशत पर पहुंच गया है। लेकिन 2015-16 में स्थिर (2011-12) कीमतों पर सेवा जीसीएफ की वृद्धि दर 7.6 प्रतिशत है जोकि 2014-15 की तुलना में लगभग आधी है। इसका मुख्य कारण रियल एस्टेट, रिहायशी और पेशेवर सेवाओं के स्वामित्व में -2.4 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि है। फिर भी सेवा जीसीएफ वृद्धि, कुल जीसीएफ वृद्धि के मुकाबले में उच्च बनी हुई है (सारणी 2)।

सेवा का राज्य-वार विश्लेषण

9.10 जिन 32 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के लिए सीएसओ द्वारा नए आधार 2011-12 श्रृंखला के लिए आंकड़े जारी किए गए हैं, वर्ष 2016-17 के लिए, उनमें से केवल 10 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के आंकड़े उपलब्ध हैं और 2015-16 के लिए 23 राज्यों के आंकड़े उपलब्ध हैं। इन 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में, सेवा क्षेत्र का वर्चस्व है, जो 16 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सकल राज्य मूल्य वर्धन (जीएसवीए) का आधे से अधिक है तथा अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड एवं सिक्किम को छोड़कर सभी राज्यों में 40 प्रतिशत से अधिक योगदान दे रहा है। अधिकतर राज्यों में मुख्य सेवाएं व्यापार, होटल और रेस्तरां हैं, जिनके पश्चात् रियल एस्टेट, रिहायशी और व्यवसाय सेवाओं के स्वामित्व का स्थान है। 23 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में से, जिनके लिए 2015-16 के लिए आंकड़े उपलब्ध हैं, सेवा जीएसवीए के भाग के अनुसार 88.4 प्रतिशत के साथ छत्तीसगढ़ का स्थान सबसे ऊपर है, जबकि 16.4 प्रतिशत की सेवा जीएसवीए वृद्धि के अनुसार झारखंड का स्थान सबसे ऊपर है (चित्र 2)।

सारणी 2. भारत के सेवा क्षेत्र का हिस्सा और इसमें वृद्धि (आधार मूल्य पर जीवीए)

	जीवीए (प्रतिशत)			जीसीएफ (प्रतिशत)	
	2014-15	2015-16	2016-17@	2014-15	2015-16
कुल सेवाएं	**51.8(9.7)**	**52.9(9.7)**	**53.8(7.7)**	**59.8(14.0)**	**60.3(7.6)**
व्यवसाय, मरम्मत, होटल तथा रेस्तरा	11.4(9.2)	11.4(11.2)	18.4(7.8)*	9.4(57.6)	10.1(16.1)
व्यवसाय और मरम्मत सेवाएं	10.4(9.4)	10.4(10.9)	NA	8.4(51.4)	8.7(11.3)
होटल तथा रेस्तरा	1.0(6.3)	1.0(14.4)	NA	1.0(140.1)	1.5(56.8)
यातायात, भंडारण, संचार और प्रसारण संबंधी सेवाएं	6.8(8.8)	7.0(9.3)	NA	6.1(-28.1)	6.4(9.9)
रेलवे	0.8(9.4)	0.8(7.0)	NA	1.7(43.1)	1.9(14.7)
सड़क यातायात	3.2(6.5)	3.2(6.7)	NA	2.0(43.1)	2.0(5.5)
हवाई यातायात	0.1(14.0)	0.2(16.8)	NA	0.2(21.6)	0.0(-92.3)
वित्तीय सेवाएं	5.7(9.0)	5.8(6.8)	21.1(5.7)^	1.6(67.4)	1.8(16.8)
रियल एस्टेट, आवासीय और पेशेवर सेवाओं का स्वामित्व	14.8(12.1)	15.3(12.5)	NA	28.8(18.9)	26.7(-2.4)
लोक प्रशासन और रक्षा तथा अन्य	13.0(8.1)	13.4(6.9)	14.2(11.3)	13.8(9.1)	15.4(20.2)
निर्माण	8.6(4.7)	8.1(5.0)	7.6(1.7)	5.5(25.0)	5.0(-2.4)
कुल सेवाएं (निर्माण सहित)	**60.4(8.9)**	**61.0(9.1)**	**61.4(6.9)**	**65.3(14.9)**	**65.3(6.7)**
आधार मूल्यों पर कुल जीवीए/जीसीएफ	**100.0(7.2)**	**100.0(7.9)**	**100.0(6.6)**	**100.0(7.5)**	**100.0(6.2)**
जीडीपी बाजार मूल्य (सतत् मूल्य) वर्षानुवर्ष	**(7.5)**	**(8.0)**	**(7.1)**		

स्रोत: **सीएसओ डाटा से संगणित।**

टिप्पणी: **हिस्से चालू मूल्यों में हैं और वृद्धि सतत 2011-12 मूल्यों में है; कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े वृद्धि दर इंगित करते हैं; @ 2016-17 के लिए अनंतिम आंकड़े; *परिवहन, भंडारण, संचार और प्रसारण संबंधी सेवाएं भी शामिल हैं; ^रियल एस्टेट, आवासीय और पेशेवर सेवाओं का स्वामित्व भी शामिल है।**

चित्र 2. राज्यों में सेवाओं का हिस्सा और वृद्धि (2016-17)

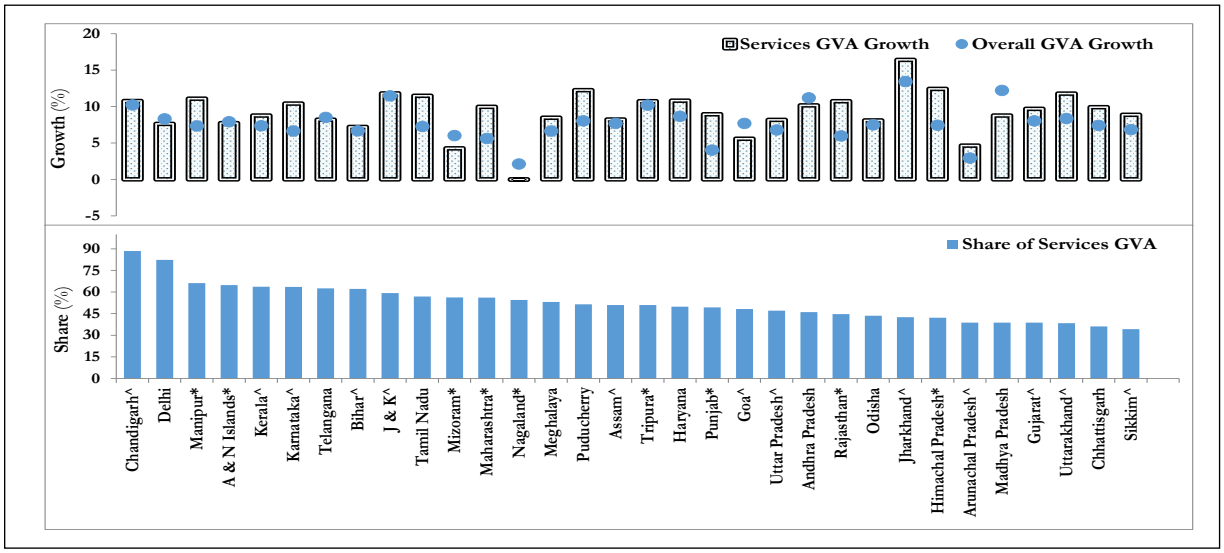

स्रोत: **सीएसओ डाटा से संगणित।**

टिप्पणी: ***2014-15, ^2015-16, चालू मूल्यों में हिस्सा और स्थिर मूल्यों (2011-12) पर वृद्धि।**

भारत के सेवा क्षेत्र में एफडीआई

9.11 यद्यपि सेवाओं में एफडीआई के वर्गीकरण में अस्पष्टता है फिर भी औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) की सेवा क्षेत्र की परिभाषा के अधीन आने वाले वित्तीय और गैर-वित्तीय सेवा जैसे शीर्ष 10 सेवा क्षेत्रों के संयुक्त एफडीआई हिस्से को; दूर-संचार; व्यापार, कम्प्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर; निर्माण; होटल और पर्यटन; अस्पताल और निदान केंद्र; परामर्शी सेवाएं; समुद्री परिवहन; तथा सूचना एवं प्रसारण सेवा एफडीआई के सर्वश्रेष्ठ अनुमान वाले क्षेत्र के रूप में लिया जा सकता है, हालांकि इनमें कुछ सेवा-भिन्न कारकों को शामिल किया जा सकता है। यह हिस्सा अप्रैल 2000 से मार्च 2017 की अवधि के दौरान संचयी एफडीआई इक्विटी अंतर्वाहों का 55.3 प्रतिशत है और 2016-17 के दौरान एफडीआई इक्विटी अंतर्वाहों का 60.7 प्रतिशत है। यदि खुदरा व्यापार, कृषि सेवाओं, शिक्षा, पत्तन और हवाई यातायात जैसी अन्य 5 सेवाओं या सेवा-संबंधी क्षेत्रों का हिस्सा शामिल किया जाता है, तो उपर्युक्त दो अवधियों के लिए सेवा क्षेत्र में एफडीआई इक्विटी अंतर्वाहों का कुल हिस्सा बढ़कर क्रमशः 57.4 प्रतिशत और 62.4 प्रतिशत हो जाएगा।

9.12 वर्ष 2014-15 और 2015-16 मे सामान्यतया (27.3 प्रतिशत और 29.3 प्रतिशत) तथा विशिष्ट रूप से सेवाएं क्षेत्र (15 शीर्ष सेवाओं के लिए 67.3 प्रतिशत और 64.3 प्रतिशत) में एफडीआई अंतर्वाहों में काफी वृद्धि हुई है। तथापि, 2016-17 में, एफडीआई इक्विटी अंतर्वाहों में वृद्धि दर सामान्य रही। कुल एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह सामान्य 8.7 प्रतिशत बढ़कर 43.5 बिलियन अमरीकी डालर पर पहुंच गया और सेवा क्षेत्र (शीर्ष 15 सेवाएं) में एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह 1.5 प्रतिशत घटकर 27.2 बिलियन अमरीकी डालर रह गया। सेवा एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह में इस नकारात्मक वृद्धि का मुख्य कारण कम्प्यूटर साफ्टवेयर और हार्डवेयर, निर्माण, व्यापार और होटल तथा पर्यटन में नकारात्मक वृद्धि रहा (सारणी 3)।

सारणी 3. सेवा क्षेत्र में एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह

		मूल्य (मिलियन यूएस$ में)	कुल का प्रतिशत (%)	वृद्धि दर (%)	
क्र.	क्षेत्र	2016-17	2016-17	2015-16	2016-17
1	सेवा क्षेत्र*	8684	20.0	55.1	26.0
2	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर	3652	8.4	157.2	-38.2
3	निर्माण #	1966	4.5	182.0	-57.5
4	कारोबार	2338	5.4	41.0	-39.2
5	होटल और पर्यटन	916	2.1	71.5	-31.3
6	दूरसंचार	5564	12.8	-54.3	320.1
7	सूचना और प्रसारण	1517	3.5	295.9	50.3
8	अस्पताल और निदान केंद्र	747	1.7	30.7	0.7
9	परामर्शी सेवाएं	261	0.6	13.0	-49.5
10	समुद्री यातायात	735	1.7	28.8	71.2
	शीर्ष 10 सेवा श्रेणियां (1-10)	**26380**	**60.7**	**62.4**	**-0.9**
	शीर्ष 15 सेवाएं	**27151**	**62.4**	**64.3**	**-1.5**
	कुल एफडीआई अंतर्वाह	**43478**	**100.0**	**29.3**	**8.7**

स्रोतः **औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग (डीआईपीपी) के आंकड़ों पर आधारित।**

टिप्पणीः *वित्तीय, बैंकिंग, बीमा, गैर-वित्तीय व्यवसाय, आउटसोर्सिंग, आरएंडडी, कोरियर, प्रौद्योगिकी परीक्षण और विश्लेषण; #अवसंरचना कार्यकलापों और टाउनशिप, आवासीय, तैयार अवसंरचना तथा निर्माण-विकास परियोजनाओं को मिलाकर।

9.13 पिछले तीन वर्षों में, सरकार ने कई सुधार किए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत निवेश के लिए उत्तरोत्तर रूप से आकर्षक स्थान बना रहे। इन सुधारों के स्तर का पता इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि इस अवधि के दौरान, सेवा कार्यकलापों को भी शामिल करते हुए 21 क्षेत्रों और एफडीआई नीति के 87 क्षेत्रों को कवर करते हुए सुधार किए गए हैं। निर्माण विकास, प्रसारण, खुदरा व्यापार, हवाई यातायात, बीमा और पेंशन जैसे क्षेत्रों से संबंधित एफडीआई नीति प्रावधानों में व्यापक सुधार किए गए थे। इसके अलावा, इस शर्त को पूरा किए बिना कि ऐसे खाद्य उत्पादों का विनिर्माण और/या उत्पादन भारत में हुआ हो, खाद्य उत्पादों के खुदरा व्यापार मे 100 प्रतिशत एफडीआई, किसी वित्तीय क्षेत्र विनियामक द्वारा विनियमित किसी वित्तीय क्षेत्र कार्यकलाप के लिए स्वचलित मार्ग के अधीन 100 प्रतिशत एफडीआई अनुमत करने के लिए एफडीआई नीति में संयोजन सीमाओं की शुरूआत करने जैसे उपाय भी किए गए थे और सबसे श्रेष्ठ सुधारात्मक उपाय हाल ही में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआइपीबी) को समाप्त करने का था।

भारत का सेवा व्यापार

9.14 वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट तक, लगभग एक दशक तक भारत के सेवा निर्यातों में काफी अच्छी वृद्धि दर्ज की गई है। सेवा निर्यात वृद्धि की 1994-95 से 2004-2005 के दौरान 21.6 प्रतिशत सीएजीआर थी, जो 2005-06 से 2014-15 के दौरान गिरकर 11.9 प्रतिशत रह गई। अनिश्चित वैश्विक परिस्थितियों और कमजोर बाहरी मांग के परिणामस्वरूप, भारत की सेवा निर्यात वृद्धि भी पांच वर्षों की अवधि के बाद 2015-16 में -2.4 प्रतिशत के साथ नकारात्मक रूप में परिवर्तित हो गई। 2016-17 में, परिवहन व्यवसाय सेवा और वित्तीय सेवाओं जैसे कुछ प्रमुख क्षेत्रों में उछाल; और यात्रा में अच्छी वृद्धि के साथ 5.7 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई (सारणी 4)। विदेशी पर्यटक आगमन, यात्रा से प्राप्तियों में काफी वृद्धि हुई, जो सेवा निर्यात के 14.2 प्रतिशत से अधिक बैठती

सारणी 4. भारत की मुख्य सेवाओं का व्यावसायिक निष्पादन

	मूल्य (बिलियन यूएस$ में)	शेयर (%)	वार्षिक वृद्धि (%)	
	2016-17	2016-17	2015-16	2016-17
सेवा निर्यात	**163.1**	**100.0**	**-2.4**	**5.7**
यात्रा	23.2	14.2	4.6	9.3
यातायात	15.9	9.7	-19.9	13.2
विविध	121.2	74.3	-0.9	4.1
सॉफ्टवेयर सेवा	73.7	45.2	1.4	-0.7
व्यवसाय सेवा	32.9	20.2	2.0	13.6
वित्तीय सेवा	5.1	3.1	-12.7	3.1
सेवा आयात	**95.7**	**100.0**	**3.7**	**13.0**
यात्रा	16.4	17.2	-3.4	11.1
यातायात	14.1	14.8	-6.8	-6.3
विविध	63.0	65.9	9.8	19.5
सॉफ्टवेयर सेवा	3.6	3.7	-0.3	32.9
व्यवसाय सेवा	32.3	33.7	12.5	3.7
वित्तीय सेवा	5.9	6.1	-12.4	86.7
निवल सेवा निर्यात	**67.5**	**100.0**	**-9.0**	**-3.2**

स्रोत: आरबीआई के भुगतान संतुलन (बीओपी) डाटा (बीपीएम-5) पर आधारित।

है जिसके परिणामस्वरूप पिछले वर्ष में 4.6 प्रतिशत की तुलना में 2016-17 में 9.3 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। 2015-16 में परिवहन सेवा निर्यात 19.9 प्रतिशत की गिरावट के विपरीत 2016-17 में 13.2 प्रतिशत तक बढ़ गया, जिससे वाणिज्यिक व्यापार कार्यकलाप में सुधार प्रतिबिंबित होता है। व्यवसाय सेवा निर्यात में पिछले वर्ष में 2 प्रतिशत की तुलना में 13.6 प्रतिशत की उच्च वृद्धि दर्ज की गई और वित्तीय सेवा निर्यात पिछले वर्ष में 12.7 प्रतिशत की गिरावट के विपरीत 3.1 प्रतिशत तक बढ़ गया। तथापि, सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात, जो कुल सेवा का 45.2 प्रतिशत बैठता है, में 0.7 प्रतिशत तक की मामूली गिरावट आई क्योंकि घरेलू कंपनियों ने परंपरागत सेवाओं पर कीमत निर्धारण के दबाव और चुनौतीपूर्ण वैश्विक व्यावसायिक माहौल का सामना किया था।

9.15 वर्ष 2016-17 में भारत के सेवा आयात में 13.0 प्रतिशत की उच्च वृद्धि दर्ज की गई थी, जो मुख्य रूप से वित्तीय सेवा और सॉफ्टवेयर श्रेणी में दो मुख्य सेवाओं, यात्रा सेवा और विविध सेवा श्रेणी के लिए किए गए भुगतानों के कारण थी। सेवा क्षेत्र में गिरावट और सेवा आयात वृद्धि में उछाल के परिणामस्वरूप 2015-16 में निवल सेवा प्राप्तियां 9.0 प्रतिशत तक घट गईं। 2016-17 में, सेवा निर्यात में 5.7 प्रतिशत की वृद्धि के बावजूद, निवल सेवा प्राप्तियां 3.2 प्रतिशत तक घट गईं जबकि यह वृद्धि सेवा निर्यातों में हुई वृद्धि के सापेक्ष उच्च थी। निवल सेवा अधिशेष से भारत के व्यापार घाटे के लगभग 60 प्रतिशत का वित्तपोषण हुआ।

सेवा व्यापार नीतियों और सेवा वार्ताओं में कुछ हालिया उपलब्धियां

बहुपक्षीय और द्विपक्षीय

9.16 इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

डब्ल्यूटीओ में सेवा में व्यापार सुविधा (टीएफएस) संबंधी भारत की प्रस्तुति: भारत ने 22 फरवरी, 2017 को डब्ल्यूटीओ में टीएफएस संबंधी विधिक मसौदा पटल पर रखा। भारत के टीएफएस प्रस्ताव के पीछे उद्देश्य डब्ल्यूटीओ में इस बात पर चर्चाएं आरंभ करना है कि सीमा और सीमा-पार के अनेक अवरोधों, आपूर्ति के सभी तरीकों का व्यापक समाधान कैसे किया जाए तथा सेवा में व्यापार को सुगम बनाने से संबंधित पारदर्शिता, सुगमता प्रक्रियाओं एवं अवरोधों को समाप्त करने जैसे प्रासंगिक मुख्य मुद्दों का समाधान कैसे किया जाए।

डब्ल्यूटीओ में मॉड 4 (सेवाओं की आपूर्ति के लिए प्रकृत व्यक्तियों के अस्थाई आधार पर आवागमन के माध्यम से व्यापार) संबंधी भारत की प्रस्तुति: भारत ने मार्च, 2016 में ''मॉड 4: एस्सेमेंट ऑफ बेरियर्स टु एंट्री'' के संबध में डब्ल्यूटीओ में एक दस्तावेज प्रस्तुत किया, जिसमें मॉड 4 प्रविष्टि में अवरोधों के बढ़ते जटिल स्वरूप का मुख्य रूप से उल्लेख किया गया। इनमें इंटरा-कॉरपोरेट अंतरितियों के अधीन उप-श्रेणियों की विषयक परिभाषाएं, जिनके चलते प्रामाणिक आवेदन रद्द होते हैं, और प्रतिबद्धताओं का महत्व कम हो जाता है तथा सामाजिक सुरक्षा योगदानों की गैर-अन्तरीयता को शामिल किया गया है।

सेवा व्यापार करार (टीआईएसए) और भारत का पक्ष: वर्तमान में, बहुपक्षीय टीआईएस चर्चाओं में 23 सदस्य भाग ले रहे हैं जिनमें ब्रिक्स और आसियान सदस्य देशों का कोई भागीदार शामिल नहीं है। भारत और भारत जैसा दृष्टिकोण रखने वाले अन्य विकासशील देशों ने इस बहुपक्षीय करार के संबंध में समय-समय पर अपनी चिंता जाहिर की है क्योंकि यह विश्व व्यापार संगठन में वर्षों की गहन वार्ता के बाद कृषि, एनएएमए और सेवा के बीच बने नाजुक संतुलन को ठेस पहुंचाकर दोहा राउंड के निष्कर्ष के लिए खतरा बन सकता है। ट्रांस-पेसिफिक भागीदारी (टीपीपी) से अमरीका के अलग हो जाने से, टीआईएसए का भविष्य भी अनिश्चित हो गया है, क्योंकि अमरीका जैसे विकसित देश इसके मार्गदर्शक हैं।

द्विपक्षीय/बहुपक्षीय करार और भारत: भारत ने सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, जापान और मलेशिया की सरकारों के साथ सेवा में व्यापार सहित व्यापक द्विपक्षीय व्यापार करारों पर हस्ताक्षर किए हैं। सेवा और निवेश में मुक्त व्यापार करार (एफटीए) पर सितंबर, 2014 में आसियान के साथ हस्ताक्षर किए गए थे, जो 01 जुलाई, 2015 से प्रभावी हुआ। हाल ही में भारत क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) बहुपक्षीय वार्ताओं में शामिल हो गया है, यह ऐसा एकमात्र मेगा-क्षेत्रीय एफटीए है जिसमें

भारत भागीदार है। भारत विभिन्न देशों के साथ सेवा में व्यापार सहित द्विपक्षीय एफटीए वार्ताओं में भागीदारी कर रहा है।

ओईसीडी में उपलब्धियां: ओईसीडी भारत सहित विभिन्न देशों के लिए सेवा व्यापार प्रतिबंधता सूचकांक (एसटीआरआई) तैयार कर रहा है। एक नई पहल होने के बाद भी, व्यापार वार्ताओं और घरेलू नीतियों के लिए इसकी उपयुक्तता की जांच किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि कुछ ऐसी चिन्ताएं हैं, जिनका समाधान किया जाना है। भारत और अन्य विकासशील देशों की चिन्ताओं पर ध्यान देने के लिए एसटीआरआई में संशोधन भी किया जा सकता है (बॉक्स 1)।

बॉक्स 1. एसटीआरआई और भारत

ओईसीडी का एसटीआरआई व्यापार को प्रतिबंधित करने वाले नीतिगत उपायों की पहचान करने, नीति निर्माताओं और वार्ताकारों को सेवा में अंतरराष्ट्रीय व्यापार उपलब्ध कराने के लिए सूचना तथा मापन युक्तियां प्रदान करने एवं अंतरराष्ट्रीय व्यापार करारों पर वार्ताएं करने और सरकारों द्वारा सर्वश्रेष्ठ परिपाटियों की पहचान करने के लिए नीतिगत उपायों को अभिचिह्नित में भी सहायक है और तत्पश्चात इसमें तरजीही क्षेत्रों तथा उपायों संबंधी उनके घरेलू सुधार प्रयासों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। इसका आशय 22 सेवा क्षेत्रों में व्यापार प्रतिबंधता के स्तर के मात्रात्मक उपाय प्रदान करना है और इसकी गणना 44 देशों के लिए की गई है। एसटीआरआई के आंकड़ों को पांच नीति क्षेत्रों में बांटा गया है: बाजार में प्रवेश शर्तों संबंधी प्रतिबंध, लोगों के आवागमन पर प्रतिबंध, अन्य विभेदकारी उपाय, प्रतिस्पर्धा संबंधी रुकावटें और विनियामक पारदर्शिता।

44 देशों में, भारत का एसटीआरआई स्कोर सभी क्षेत्रों में औसत से अधिक है और कुल 22 क्षेत्रों में से 3 सेवाओं में सबसे अधिक है (चित्र 3)। साउंड रिकार्डिंग, अभियांत्रिकी और प्रसारण ऐसे तीन क्षेत्र हैं जहां स्कोर औसत से कम है। इन सभी तीनों क्षेत्रों में 100 प्रतिशत इक्विटी शेयर तक स्वचलित मार्ग का अनुसरण किया जाता है। लेखांकन सेवाएं, विधिक सेवाएं और रेल भाड़ा यातायात ऐसे तीन क्षेत्र हैं, जहां स्कोर औसत से सबसे अधिक है क्योंकि लेखांकन और लेखापरीक्षा सेवाएं लाइसेंसधारी लेखाकारों और लेखापरीक्षकों के लिए आरक्षित हैं और किसी लेखांकन तथा लेखापरीक्षा फर्म के मालिकाना हक और प्रबंधन के लिए लाइसेंस की अपेक्षा होती है और ऐसा लाइसेंस केवल भारतीय नागरिक प्राप्त कर सकते हैं; विधिक सेवाएं, (राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विधि दोनों), लाइसेंसधारी भारतीय अधिवक्ताओं के लिए आरक्षित हैं; तथा रेलवे प्रचालन ख्जो प्रतिषिद्ध सूची में दिए गए हैं और भारतीय रेलवे के लिए आरक्षित हैं, जो केंद्र सरकार का उद्यम है। तथापि, भारत में एफआईपीबी के समापन जैसे कुछ हालिया सुधारों पर इन आंकड़ों में विचार नहीं किया गया है।

चित्र 3: सर्वोच्च, निम्नतम और औसत एसटीआरआई की तुलना में भारत का एसटीआरआई (2016)

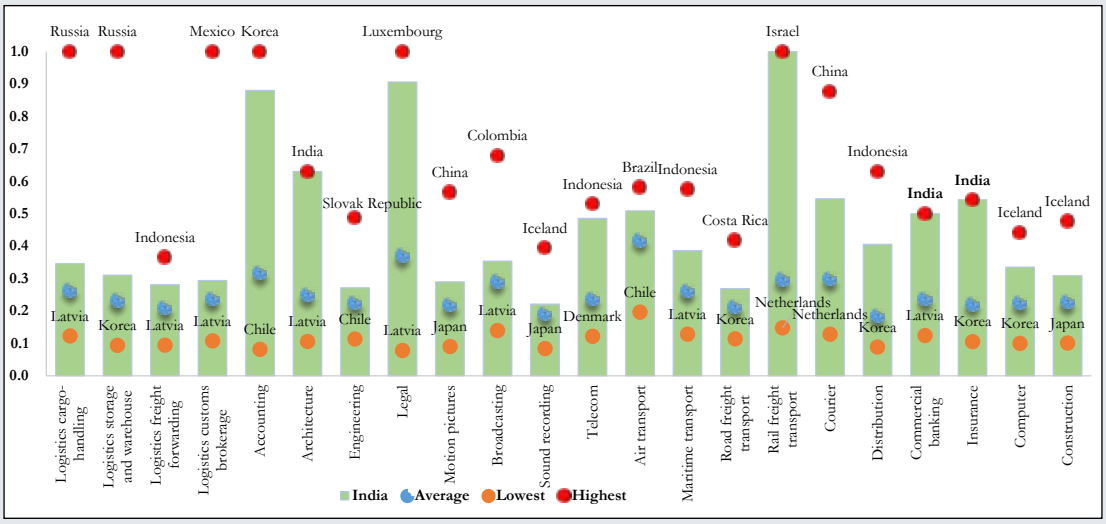

भारत अनेक क्षेत्रों में उच्च एसटीआरआई रखता है। चीन के मामले में, चलचित्रों, प्रसारण, और कूरियर सेवाओं जैसे कुछ क्षेत्रों में भारत से उच्च एसटीआरआई है।

एसटीआरआई, ओईसीडी द्वारा सेवा के लिए नयी पहल है। तथापि, एसटीआरआई और इसके उपयोग से जुड़ी हुई कुछ अंतर्निहित कमियां हैं। विनियमनों का महत्व और गुणवत्ता ज़रूरी है, क्योंकि घरेलू विनियमन सभी देशों में एकरूप नहीं हैं और यह ज़रूरी है कि आवश्यक विनियमनों तथा व्यापार बाधक विनियमनों में अंतर किया जाए। चूंकि समान सेवाओं के लिए भी व्यापार अवरोध विभिन्न देशों में एक समान नहीं हैं, अत: विशेषज्ञों द्वारा भी उन्हें महत्व दिया जाना मनमानीपूर्ण हो जाता है।

जहां एसटीआरआई में कुछ प्रतिबंध वस्तुत: प्रतिबंध नहीं हैं और वे ब्रॉड बैंड की अनुपलब्धता के मामले की तरह अवसंरचना के विकास की कमी के कारण ही हैं, वहीं कुछ प्रतिबंध सामाजिक और आर्थिक समावेशन जैसे बैंकों से अपने निवल जमा का 40: प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में, जैसे कि भारत में कृषि, और एसएमई, शिक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा हेतु आबंटित करना अपेक्षित है, से संबंधित सरकार की नीति के कारण हो सकते हैं। एसटीआरआई, ओईसीडी द्वारा इंगित सेवाओं में विनियमों के समतुल्य कर और प्रशुल्क की परिकलना के लिए लागू नहीं किया जा सकता, खासकर जब आंकड़े अपूर्ण हों और विनियम एकरूप नहीं हों।

इस प्रकार, एसटीआरआई अधिक से अधिक संकेतकारी ही हो सकता है और इसे संख्यात्मक महत्त्व नहीं दिया जा सकता, खासकर तब जब अनेक देशों के लिए सेवा से संबंधित आंकड़े प्रारंभिक स्तर पर हों और कार्यप्रणाली की परिपूर्णता में त्रुटियां हों। टीएफएस और बाजार तक पहुंच उतने ही महत्त्वपूर्ण हैं जितना घरेलू व्यापार अवरोध दूर करना। दरअसल, उपर्युक्त तीनों में कुछ हद तक प्रतिच्छादन भी है।

***स्रोत:* ओईसीडी एसटीआरआई प्रतिवेदनों और आंतरिक विश्लेषणों पर आधारित**

घरेलू

9.17 भारत द्वारा सेवा क्षेत्र के लिए निर्मित हालिया घरेलू नीतियों और की गई कार्रवाइयों में निम्नलिखित शामिल हैं:–

व्यापार नीति उपाय: इसमें सर्व्ड फ्राम इंडिया स्कीम (एसएफआईएस) को प्रतिस्थापित करते हुए सर्विसेज एक्सपोर्ट्स फ्राम इंडिया स्कीम (एसईआईएस), जिसमें अर्जित निवल विदेशी मुद्रा का 3 प्रतिशत या 5 का प्रतिफल मोड 1 और मोड 2 सेवाओं के लिए दिया जाता है, पर्यटन और जहाजरानी जैसे क्षेत्रों के लिए प्रवर्तित स्कीमें और सेवा क्षेत्र के लिए डिजिटाइजेशन तथा एफडीआई उदारीकरण सरीखे सामान्य उपाय शामिल हैं।

वस्तु और सेवा कर: जीएसटी के अंतर्गत निर्यात शुल्क दर शून्य रहेगी। सेवाओं के विषय में जीएसटी की मुख्य व्यवसाीएं इस प्रकार है: शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर दर शून्य होगी; किफायती श्रेणी में हवाई यात्रा पर यह 5 प्रतिशत रहेगी, यही दर रेल तथा समुद्री मार्ग से वस्तुओं के परिवहन पर देय होगी(एसी तथा केंद्रीय तापन प्रणाली तथा शराब बेचने की अनुमति से रहित रेस्त्रां में भोजन एवं पेय पदार्थों की बिक्री पर यह दर 12% होगी [किन्तु इन व्यवस्थाओं वाले रेस्त्रां में जीएसटी दर 18 प्रतिशत रहेगी], होटल, गैस्ट हाऊस जहां प्रतिदिन रु. 1000/- से रु. 2500/- तक पर कमरे मिलते हैं, वहां भी ये दर 12% है (वहीं रु. 2500/- से रु. 7500/- प्रतिदिन वाले कमरों पर देय दर 18%) रखी गई है। इसी प्रकार गैरकिफायती वायुयान यात्रा, किसी भवन कंपलैक्स और आईटीसी के प्रतिदाय की व्यवस्था के बिना निर्माण पर भी 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। केवल 4 सेवाएं 28 प्रतिशत जीएसटी के उच्च तय वर्ग में हैं–इनमें शामिल है: मनोरंजक कार्यक्रम, मनोविनोद स्थलों/सुविधाओं में प्रवेश [सिनेमाघरों सहित], थीम पार्क, जलक्रीड़ा पार्क, और निवास आदि के लिए प्रतिदिन रु. 7500/- से अधिक प्रभार लेने वाले होटल/अतिथिगृह आदि।

संवर्धन उपाय: भारत सरकार द्वारा किए गए कुछ संवर्धन उपायों में 73 देशों की भागीदारी के साथ बहु-क्षेत्रक वैश्विक सेवा प्रदर्शनी (जीईएस) का अप्रैल 2017 में तीसरे दौर का आयोजन करना तथा भारत को अग्रणी वैश्विक स्वास्थ्य परिचर्या गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने हेतु चिकित्सा महत्व यात्रा पर अंतरराष्ट्रीय शिखर बैठक के नाम से एडवाण्टेज़ हैल्थ केयर इंडिया 2016 के दूसरे दौर का आयोजन अक्तूबर, 2016 में करना शामिल है।

प्रमुख सेवाएं: समग्र निष्पादन

9.18 भारत के सेवा क्षेत्र का निष्पादन वैश्विक रुझान के अनुरूप ही 2016-17 में मंद पड़ गया है। तथापि, कुछ सेवाएं भारत के आर्थिक विकास में मुख्य वाहक बनी हुई हैं। भारत में विभिन्न उप क्षेत्रों के 2016-17 के लिए वाहक उपलब्ध कुछ संकेतकों (सारणी 5) तथा सीएमआईई आंकड़ों (सारणी 7) को देखने से पता चलता है कि जियो प्रभाव को प्रतिबिम्बित कर रहे दूरसंचार कनेक्शनों में वृद्धि के साथ दूरसंचार में, खासकर घरेलू यात्रा के विमानन में, विशेष रूप से विदेशी मुद्रा के अर्जन की दृष्टि से पर्यटन संबंधी सेवाओं में, और कम्प्यूटर साफ्टवेयर की वृद्धि में गिरावट के बावजूद सूचना प्रौद्योगिकी व्यवसाय प्रक्रिया प्रबंधन (आईटीबीपीएम) में उचित रूप से अच्छा निष्पादन हुआ है।

सारणी 5. भारत के सेवा क्षेत्र का निष्पादन: कुछ संकेतक

क्षेत्र	संकेतक	यूनिट	अवधि				
			2009-10	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
आईटी-बीपीएम**	आईटी-बीपीएम सेवा राजस्व	यूएस $ बिलियन	64	106	119	143	154
	निर्यात	यूएस $ बिलियन	50	87	98	108	117
	घरेलू	यूएस $ बिलियन	14	19	21	35	38
विमानन*	एयरलाइन यात्री (कुल)	मिलियन	77.4	103.8	115.8	135.0	158.4
	घरेलू	मिलियन	45.3	60.7	70.1	85.2	103.7
	अंतरराष्ट्रीय	मिलियन	32.1	43.1	45.7	49.8	54.7
दूरसंचार	दूरसंचार कनेक्शन (वायरलाइन और वायरलैस)[b]	मिलियन	621.3	933.0	996.1	1058.9	1194.6
पर्यटन	विदेशी पर्यटक आगमन[a]	मिलियन	5.2	7.0	7.7	8.0	8.8
	पर्यटन से विदेशी मुद्रा आय[a]	यूएस $ बिलियन	11.1	18.4	20.2	21.1	22.9
जहाजरानी	भारतीय जहाजरानी का सकल टनभार[b]	मिलियन जीटी	9.7	10.5	10.5	10.5	12.0[@]
	जहाजों की संख्या[b]	संख्या	998	1209	1210	1251	1338[@]
पत्तन	पत्तन यातायात	मिलियन टन	850.0	972.5	1052.5	1072.5	1135.6

स्रोत: **भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई), पर्यटन मंत्रालय, जहाजरानी मंत्रालय, नागर विमानन महानिदेशालय, एनएएसएससीओएम से संकलित।**

टिप्पणी: **[a]कलैंडर वर्ष, उदाहरणार्थ 2009-10 के लिए 2009; [b]आगामी वित्त वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार; @30 जून, 2017 की स्थिति के अनुसार डाटा। जीटी = सकल टनभार; एमटी = मैट्रिक टन; **हार्डवेयर को छोड़कर। *घरेलू यात्रियों का आवागमन केवल अनुसूचित घरेलू सेवाओं पर अनुसूचित भारतीय वाहकों द्वारा हुआ और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों का आवागमन भारतीय राज्यक्षेत्र में और से अनुसूचित भारतीय एवं विदेशी वाहकों द्वारा हुआ।**

9.19 विमानन उद्योग ने देशी-विदेशी यात्रियों सहित, कुल यात्री संख्या की दृष्टि से, पिछले वर्ष की अपेक्षा वर्ष 2016-17 में 17.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करके बेहतर प्रदर्शन किया। नए घरेलू और विदेशी मार्गों के अतिरिक्त एयरलाइनों की क्षमता में वृद्धि होने तथा क्षेत्रीय हवाई संपर्क (संयोजकता) स्कीम (आरसीएस) नामक उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना के प्रर्वतन से इस क्षेत्र को और अधिक बढ़ावा मिलने की संभावना है, क्योंकि यह योजना उन असेवित तथा अल्प सेवित विमानपत्तनों को जोड़ करके उड़ान खर्च सहज बनाने का प्रयास करती है, जहां उपभोक्ताओं की खर्च योग्य आय में बढ़त तथा विमान भाड़े में कमी के चलते 50 प्रतिशत सीटों का उच्चतम भाड़ा 2500 रु॰ प्रति सीट/घंटा किया गया है। परिवहन संभार तंत्र सेवा के मामले में, निष्पादन, संभार तंत्र पर सरकार का ध्यान बढ़ जाने से बेहतर हो गया है। जीएसटी का प्रभाव वैट से संबंधित चेकपोस्ट के हट जाने के कारण अनुमानत: सकारात्मक रहने वाला है जिसके परिणामस्वरूप इसमें लगने वाले समय में कमी आएगी। इसके अतिरिक्त, मालों की अंतरराज्य बिक्री पर लगा हुआ 2 प्रतिशत का अतिरिक्त केंद्रीय बिक्री कर अब जारी नहीं रहेगा जिससे अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। तथापि, जहाजरानी सेवा क्षेत्र पर 2016-17 के विक्रय और पीएटी आंकड़ों द्वारा किए गए संकेत के अनुसार वैश्विक मंदन का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। व्यापार और जहाजरानी सेवा की मजबूती दर्शाने वाली माल भाड़ा सूची और अच्छा प्रतिपत्र नामक दि बाल्टिक ड्राई इंडेक्स 20 मई, 2008 को 11,793 के शीर्ष से 8 दिसंबर, 2008 को गिरकर 663 के निम्न स्तर पर आ गया था। यद्यपि इसमें आगामी वर्षों के दौरान मामूली वृद्धि हुई, तथापि यह तब से निम्नतर दायरे में रहा है और यह 11 फरवरी 2016 की स्थिति के अनुसार 290 पर खतरे की स्थिति में रहा, जो 2008 के निम्न स्तर से

चित्र 4. बाल्टिक ड्राई इंडेक्स

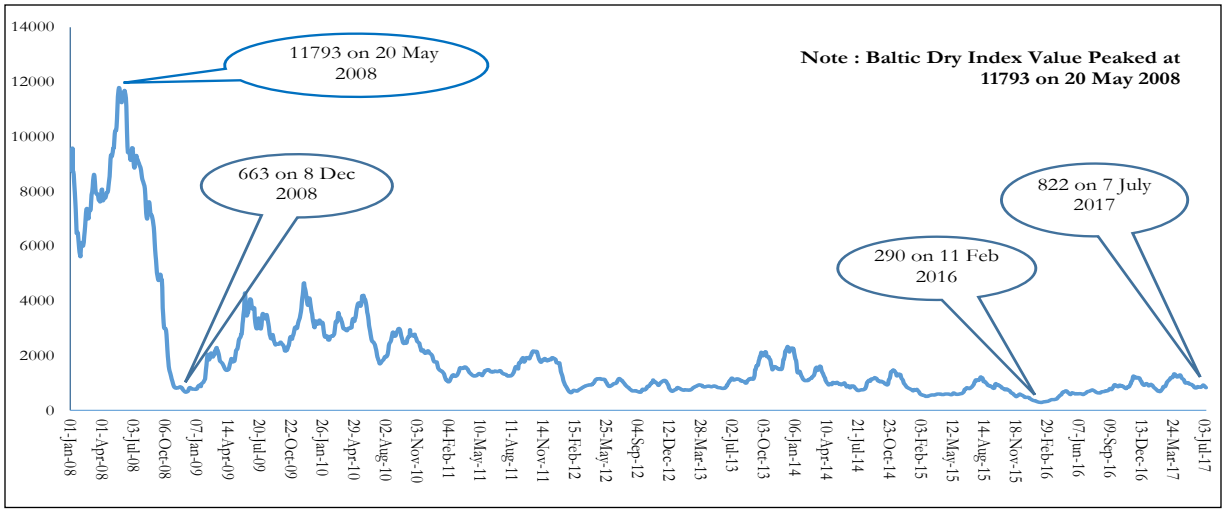

स्रोत: **https://in.investing.com/indices/baltic-dry-historical-data से डाटा पर आधारित।**

भी नीचे है। यह 7 जुलाई, 2017 को 822 पर पहुंचकर मामूली रूप से सुधर पाया है (चित्र 4)।

9.20 पत्तनों द्वारा संचालित किया गया यातायात 2015-16 में 606.5 मि॰ मीट्रिक टन से बढ़ कर 2016-17 में 647.7 मि॰ मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। प्रमुख पत्तनों के पत्तन से संबंधित निष्पादन सूचकांक भी यह दर्शाते हैं कि 2015-16 में शिप बर्थ डे उत्पाद में 13156 टन से 2016-17 में 14576 टन तक का महत्वपूर्ण सुधार हुआ है, औसत टर्न अराउंड समय और औसत प्रीबर्थिंग समय 2012-13 में 2.55 दिन और 12.17 घंटे से घटकर 2016-17 में क्रमशः 2.05 दिन और 5.75 घंटे रह गया है तथा प्रमुख पत्तनों में संचालन आधिक्य में 2015-16 की तुलना में 2016-17 के दौरान 14 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज की गई है (सारणी 6)।

9.21 विमुद्रीकरण के तुरंत बाद वाली 2016-17 की चौथी तिमाही में सेवा क्षेत्र फर्मों के परिणामों के विश्लेषण से पता चलता है कि जिस एकमात्र क्षेत्र में संकुचन का लक्षण दिखाई दिया, वह निर्माण और भवन संपदा क्षेत्र था, और इसमें चौथी तिमाही के दौरान निवल बिक्री (-5.1 प्रतिशत) और निवल लाभ (-34.9 प्रतिशत) दोनों में वर्षानुवर्ष गिरावट देखी गई। यहां पर भी, संकुचन का यथेष्ट कारण विमुद्रीकरण के प्रभाव को ही नहीं बताया जा सकता, यह मानते हुए कि इस क्षेत्र की वृद्धि पिछली दो तिमाहियों में भी पहले से ही ऋणात्मक में रही थी।

प्रमुख सेवाएं: क्षेत्रवार निष्पादन और कुछ हालिया नीतियां

9.22 इस खंड में भारत के लिए जरूरी कुछ सेवाओं को जीडीपी/जीवीए, रोजगार, निर्यात और भविष्य की संभावनाओं की दृष्टि से उनके महत्व के आधार पर वर्णित किया गया है। दूसरे अध्यायों में उल्लिखित कुछ ज़रूरी सेवाएं दुहराव से बचने के लिए इसमें शामिल नहीं की गई हैं।

सारणी 6. भारत में मुख्य पत्तनों के कुछ निष्पादन संकेतक

संकेतक	2014-15	2015-16	2016-17
संभाला गया यातायात (एमएमटी में)	581.3	606.5	647.7
प्रति-जहाज प्रति बर्थ दिन औसत आउटपुट (टनों में)	12458	13156	14576
संचालन अधिशेष (करोड़ रुपए में)	3599.4	4309.1	4919.4

स्रोत: **जहाजरानी मंत्रालय से प्राप्त सूचना पर आधारित।**

सारणी 7. चुनिंदा सेवाओं की बिक्री और लाभों में वृद्धिः कंपनी आधारित डाटा

सेवा	निवल बिक्री						कर पश्चात् लाभ (पीएटी)					
	2015-16	2016-17	2016-17				2015-16	2016-17	2016-17			
			Q1	Q2	Q3	Q4			Q1	Q2	Q3	Q4
यातायात संभारतंत्र	2.7	2.8	0.5	0.6	4.1	5.6	4.3	-3.9	-15.9	-13.0	-13.3	21.4
जहाजरानी	2.5	-10.9	-17.4	-22.0	-1.4	0.6	37.2	-8.7	-29.4	-48.5	-29.8	434.1
विमानन	39.3	33.1	75.9	73.5	8.3	9.9	--	-12.8	178.9	168.3	-40.5	-51.0
खुदरा कारोबार	22.3	61.9	38.2	35.9	34.4	178.1	2472.8	102.1	--	14.5	-45.0	--
स्वास्थ्य सेवाएं	35.0	33.9	50.9	58.2	21.3	15.9	39.1	17.3	73.4	129.8	-49.6	-3.6
होटल एवं रेस्तंरा	6.5	2.8	0.8	6.0	3.9	1.0	--	103.3	--	--	-12.1	2543.7
आईटीईएस	12.7	10.5	18.7	7.9	6.4	10.1	22.5	6.3	34.9	18.9	20.1	-28.3
सॉफ्टवेयर	10.7	9.7	13.3	9.1	9.8	6.8	11.6	8.6	7.7	6.2	12.7	7.9
निर्माण एवं रियल एस्टेट	8.3	-1.8	7.7	-6.5	-0.9	-5.1	-11.6	0.4	--	18.5	--	-34.9

***स्रोतः* एक्जिम बैंक रिसर्च (सीएमआईई से प्राप्त डाटा)।**

पर्यटन

9.23 पर्यटन में बृहत पैमाने पर विविध प्रकार के अत्यंत विशिष्टीकृत से लेकर अकुशल तक रोजगार सृजित करने; आर्थिक वृद्धि को आगे बढ़ाने; और देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने की महती क्षमता है। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल (डब्ल्यूटीटीसी) के अनुसार, यात्रा और पर्यटन ने 7.6 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर (वैश्विक जीडीपी का 10.2 प्रतिशत) और 292 मिलियन नौकरियों के सृजन द्वारा अपनी समुत्थान शक्ति को 2016 में बनाए रखा, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था के अंदर 10 नौकरियों में 1 के समतुल्य सृजन हुआ। यह क्षेत्र में कुल वैश्विक निर्यातों का 6.6 प्रतिशत और कुल वैश्विक सेवा निर्यातों का करीब-करीब 30 प्रतिशत बैठता है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडब्ल्यूटीओ) का नवीनतम वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर (मार्च, 2017 संस्करण) भी यह दिखाता है कि अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आगमन 2016 में कुल 1.2 बिलियन तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष में उनकी संख्या से 47 मिलियन अधिक है, यद्यपि इसमें 3.9 प्रतिशत की वृद्धि दर, 2015 की वृद्धि दर (4.5 प्रतिशत) से मामूली कम थी।

9.24 यूएनडब्ल्यूटीओ के अनुसार, भारत में अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आगमन (अनिवासी भारतीयों के आगमन सहित) 2015 में 1.4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 13.3 मिलियन था, जबकि पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2015 और 2016 के दौरान विदेशी पर्यटक आगमन (एफटीए) (अनिवासी भारतीयों को छोड़कर) 2015 में 4.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 8.0 मिलियन और 2016 में 9.7 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 8.8 मिलियन था। 2016 में पर्यटन के जरिए अमरीकी डालर के हिसाब से विदेशी मुद्रा अर्जन (एफईई) 2015 की अपेक्षा 8.8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 22.9 बिलियन अमरीकी डालर था। यूएनडब्ल्यूटीओ के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन प्राप्तियां (आईटीआर), लगभग इसके समान ही हैं(सारणी 8)।

भारत की अप्रयुक्त पर्यटन संभावनाः तुलनात्मक विवेचन

9.25 दूसरे देशों से तुलना करें तो यह पता चलता

है कि अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आगमन (आईटीए) में भारत का हिस्सा 2015 में प्रथम स्थान पर रहने वाले फ्रांस के 7.1 प्रतिशत के हिस्से की तुलना में 24वें स्थान पर रहने के साथ मामूली 1.1 प्रतिशत है। चीन का स्थान 4.8 प्रतिशत के हिस्से के साथ चौथा है। अंतरराष्ट्रीय पर्यटक प्राप्तियों (आईटीआर) के अनुसार, भारत का हिस्सा मामूली रूप में उच्च होकर 1.8 प्रतिशत है और इसका स्थान सुधर कर 14वां हो गया है। परंतु यह प्रथम स्थान पर रहने वाले अमरीका के 17.1 प्रतिशत हिस्से के आगे कहीं भी नहीं टिकता और चौथे स्थान पर रहने वाले चीन के 3.8 प्रतिशत हिस्से का लगभग आधा है (सारणी 8 देखें)।

9.26 घरेलू पर्यटन 1991 से 2016 तक के 13.6 प्रतिशत, और 2016 में 12.7 प्रतिशत की सीएजीआर वृद्धि के साथ इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बना हुआ है। जिन शीर्ष पांच राज्यों में घरेलू पर्यटक 2016 में पधारे, वे तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, और कर्नाटक थे। इस उद्योग के अनुमान के अनुसार, भारतीय पर्यटन और अतिथि सत्कार के बाजार का कुल धनराशि आकार 2014 में 117.7 बिलियन अमरीकी डालर बैठता था और इसके 2022 तक 418.9 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंचने की आशा है। इस प्रकार, एक समृद्धिप्रद अवसर वास्तविक उपयोग की प्रतीक्षा कर रहा है।

9.27 यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2017 (डब्ल्यूईएफ, 2017) के अनुसार, भारत ने विश्व के 136 देशों में 12 स्थानों का सुधारकर 40वां स्थान प्राप्त कर लिया है। भारत अपने व्यापक सांस्कृतिक और प्राकृतिक संसाधनों (क्रमश: 9वां और 24वां स्थान), और अपने कीमत प्रतिस्पर्धात्मकता लाभ (10वां स्थान), अपने अंतरराष्ट्रीय खुलेपन (55वां स्थान) जो आगमन पर वीजा और ई-वीजा दोनों के कार्यान्वयन को प्रदर्शित करते हुए 14 स्थान ऊपर है, के कारण अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए मनोरम बना हुआ है। परंतु यह स्वास्थ्य और स्वच्छता (104वां स्थान), आईसीटी तत्परता (112वां स्थान), सुरक्षा सरोकार (114वां स्थान), मानव संसाधन (87वां स्थान), पर्यटक सेवा ढांचा (110वां स्थान) और यात्रा तथा पर्यटन की प्राथमिकता (104वां स्थान) के मामले में अन्य देशों से बहुत पीछे है।

9.28 यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थलों की संख्या तथा विभिन्न देशों के कुल विदेशी पर्यटक आगमनों की तुलना करने से ज्ञात होता है कि यूनेस्को के वैश्विक

सारणी 8. पर्यटन निष्पादन: अंतरराष्ट्रीय तुलना 2015 और 2016

	अंतरराष्ट्रीय पर्यटन आगमन					अंतरराष्ट्रीय पर्यटन प्राप्तियां				
	रैंक	संख्या (मिलियन में)	हिस्सा (%)	वृद्धि दर (%)		रैंक	मूल्य(यूएस$ बिलियन)	हिस्सा (%)	वृद्धि दर (%)	
	2015	2016	2015	2015	2016	2015	2016	2015	2015	2016
विश्व		1235	100	4.5	3.9		1,194*	100.0	-4.5	--
फ्रांस	1	84.5*	7.1	0.9	--	3	43.1	3.8	-21.0	-6.1
यूएसए	2	77.5*	6.5	3.3	--	1	206.8	17.1	6.9	1.1
स्पेन	3	75.6	5.8	5.5	10.4	2	60.3	4.7	-13.2	6.7
चीन	4	59.3	4.8	2.3	4.2	5	44.4	3.8	2.3	-1.3
टर्की	6	39.5*	3.3	-0.8	--	12	18.7	2.2	-10.1	-29.7
थाइलैंड	10	32.6	2.5	20.6	9.0	6	49.9	3.8	16.9	11.1
मलेशिया	14	26.8	2.2	-6.3	4.3	17	16.9	1.5	-22.6	-3.4
भारत	24	13.3*	1.1	1.4	--	14	22.4	1.8	6.6	6.7
सिंगापुर	28	12.9	1.0	1.6	6.6	19	18.4	1.4	-13.1	10.8

स्रोत: यूएनडब्ल्यूटीओ वर्ल्ड टूरिजम बैरोमीटर एंड स्टेटिस्टिक्ल एनेक्स, मार्च 2017 में दिए गए आंकड़ों पर आधारित।
*टिप्पणी:** = 2015 डाटा।

विरासत स्थलों (35 स्थलों सहित 6ठा स्थान) की उच्च संख्या वाला देश होने के बावजूद, भारत अन्य देशों की अपेक्षा कम विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करता है और रुझान-रेखा के नीचे पड़ा हुआ है (चित्र 5)।

9.29 जनसंख्या में घरेलू पर्यटन अनुपात, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (कन्वेंशन) में स्थान निर्धारण, शीर्ष विरासत स्थलों में आगंतुकों, बड़े शहरों में विदेशी पर्यटक आगमनों जैसे अनेक दूसरे संकेतकों के अनुसार भी, भारत अमरीका और चीन से काफी पीछे हैं (सारणी 9)।

चित्र 5. विश्व धरोहर स्थलों और 2015 में अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन की संख्या

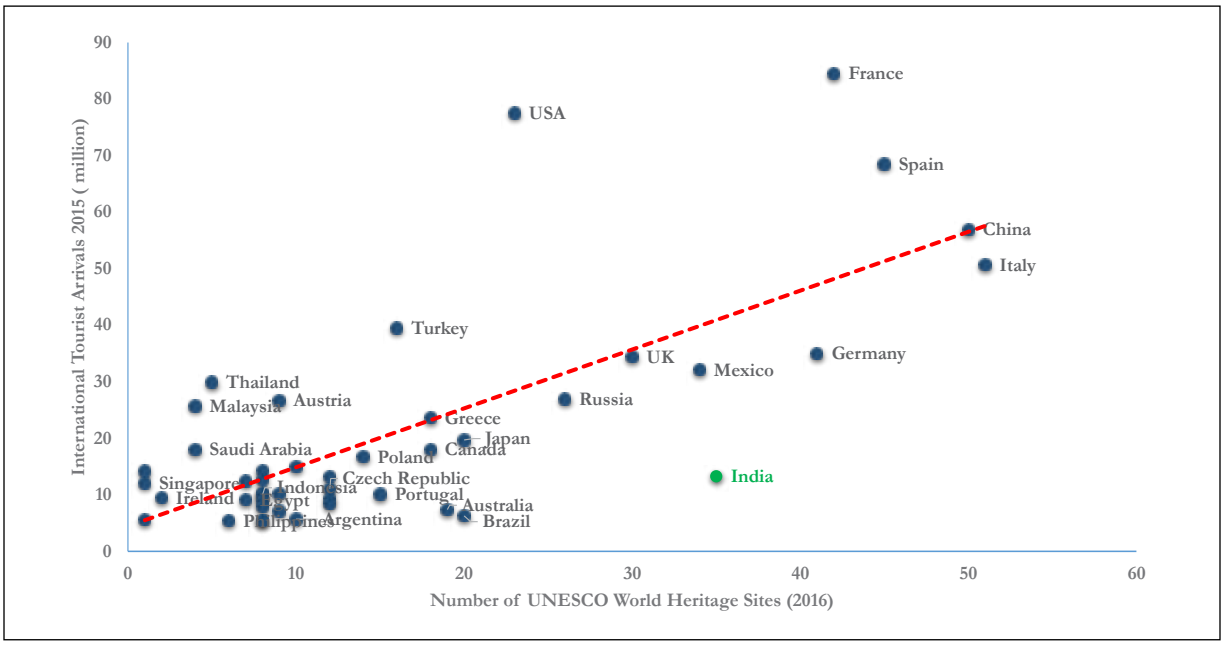

स्रोत: **यूएनडब्ल्यूटीओ और यूएनईएससीओ डाटा पर आधारित।**

सारणी 9. तुलनात्मक पर्यटन निष्पादन संकेतक

संकेतक	चीन	भारत	यूएसए
धरोहर स्थलों का दौरा करने वाले विदेशी आगुंतक (संख्या)	ग्रेट वॉल* (कुल 10 मिलियन, 03 मिलियन विदेशी)	ताज महल (कुल 4.6 मिलियन, 0.5 मिलियन विदेशी)	स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी* (कुल 5 मिलियन, 02 मिलियन विदेशी)
घरेलू पर्यटन (संख्या)	3.6 बिलियन	1.7 बिलियन	2.2 बिलियन
जनसंख्या के मुकाबले घरेलू पर्यटन का अनुपात	2.6	1.3	6.6
मुख्य शहरों में विदेशी पर्यटकों का आगमन	बीजिंग* (4.5 मिलियन विदेशी, 250 मिलियन घरेलू)	नई दिल्ली* (2.4 मिलियन विदेशी, 25 मिलियन घरेलू)	न्यूयार्क* (10.1 मिलियन विदेशी, 50 मिलियन घरेलू)
अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन रेटिंग	333 बैठकों के साथ रैंक 9	132 बैठकों के साथ रैंक 31	925 बैठकों के साथ रैंक 1

स्रोत: **यूएनडब्ल्यूटीओ, पर्यटन मंत्रालय, रिपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल कांग्रेस एंड कन्वेंशन एसोसिएशन (आईसीसीए) जैसे विभिन्न आंकड़ा स्रोतों से संकलित,**

नोट: *** = फेथ से प्राप्त सूचना।**

9.30 उपर्युक्त विश्लेषण और संकेतक, यद्यपि इनमें से कुछ कम पूर्ण हैं, यह दर्शाते हैं कि भारत में पर्यटन की विपुल संभावना है और भारत को एक प्रमुख पयर्टन गन्तव्य बनाकर बड़ी मात्रा में कमाई करने वाला देश बनाने के लिए अभी काफी कुछ किया जाना आवश्यक है।

9.31 देश के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अनेक पहलें की गई हैं जिनमें 161 देशों के नागरिकों के लिए ई-वीजा, 365 दिन के गंतव्य के रूप में भारत का प्रचार, स्वच्छता कार्ययोजना (एसएपी), कौशल विकास पहल, बहु-भाषायी पर्यटक इन्फोलाइन का प्रारंभ किया जाना, और स्वच्छ पर्यटन मोबाइल ऐप शामिल हैं। जनवरी से दिसम्बर, 2016 के दौरान कुल 10,79,696 ई-वीजा धारकों ने भारत का दौरा किया जिससे 2015 की तुलना में 142.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। ई-वीजा की अनुमति 3 उप-श्रेणियों: ई-पर्यटक वीजा, ई-व्यवसाय वीजा, और ई-चिकित्सा वीजा के तहत दी जाती है। ई-वीजा के तहत आवेदन करने के लिए विंडो की अवधि 30 दिन से बढ़ाकर 120 दिन कर दी गई है और ई-वीजा के तहत भारत में ठहरने की अवधि भी 30 दिन से बढ़ाकर 60 दिन कर दी गई है। वैश्विक रूप से, 2019 में चिकित्सा महत्त्व यात्रा (एमवीटी) बाजार द्वारा 19.4 प्रतिशत के सीएजीआर पर बढ़कर 100 बिलियन अमरीकी डालर को पार करने की संभावना है तथा 2014 में भारत का हिस्सा वैश्विक चिकित्सा पर्यटकों का 3.8 प्रतिशत और मध्यम पर्यटन से वैश्विक राजस्व का 5.5 प्रतिशत बैठता था। सरकार ने भारत को एक चिकित्सा महत्त्व यात्रा गंतव्य बनाने के लिए अनेक नीतियां प्रारंभ की हैं। इनमें 2015 में राष्ट्रीय चिकित्सा एवं आरोग्य पर्यटन संवर्धन बोर्ड का गठन और ई-पर्यटक वीजा तथा एम-वीजा सुविधाओं का प्रारंभ किया जाना शामिल है।

आईटी-बीपीएम सेवाएं

9.32 वर्ष 2016 में हार्डवेयर सहित और रहित वैश्विक आईटी-बीपीएम बाजार क्रमश: 2.2 ट्रिलियन अमरीकी डालर और 1.2 ट्रिलियन अमरीकी डालर पर स्थिर रहा। हार्डवेयर खंड का हिस्सा लगभग 44 प्रतिशत के साथ सर्वाधिक था, इसके बाद आईटी सेवाओं (29 प्रतिशत से अधिक), पैकेजयुक्त सॉफ्टवेयर (लगभग 19 प्रतिशत) और बीपीएम (8 प्रतिशत से अधिक) का स्थान था। जबकि ये परम्परागत खंड रहे हैं, इस उद्योग को उन डिजिटल प्रौद्योगिकियों से व्यवधान हो रहा है जिनसे प्रक्रियाओं के ऑटोमेशन, [विनिर्माण में ऑटोमेशन की लहर] का पथ प्रशस्त हो रहा है और वह कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो मनुष्यों के स्थान पर रोबोटों को प्रतिस्थापित कर रही है।

9.33 वर्तमान में भारतीय आईटी-बीपीएम उद्योग एक वैश्विक शक्तिगृह है और भारत तथा विश्व पर इसका प्रभाव अप्रत्याशित है। भारत का अपतटीय मॉडल उत्कृष्ट है और वर्तमान में इसे प्रौद्योगिकी और व्यवसाय समाधानों के लिए विकल्प के भागीदार के रूप में देखा जाता है। यह उद्योग 1980 में 1 बिलियन अमरीकी डालर से भी कम के स्तर से 154 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक के एक विशालकाय उद्योग के रूप में विकसित हो चुका है। विगत दशक में, इस उद्योग ने राजस्व की दृष्टि से छह गुणा से भी अधिक वृद्धि की है। 2016-17 में 3.9 मिलियन से अधिक लोगों को रोजी-रोटी प्रदान करते हुए, इस क्षेत्र ने परिवहन, होटलों, अवसंरचना, सुरक्षा सेवाओं, जैसे सहायक क्षेत्रों में भी रोजगार सृजित किया है। भारतीय आईटी-बीपीएम उद्योग में कई बिलियन डालर वाली फर्मों से लेकर स्टार्ट अप्स तक भिन्न-भिन्न प्रकार की 16,000 से अधिक फर्म सम्मिलित हैं। 1000 से अधिक वैश्विक इन-हाउस केंद्रों सहित अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां तथा लगभग 4,750+ स्टार्ट अप्स के साथ है, जिससे भारत विश्व का तीसरा विशालतम स्टार्ट अप पारिस्थितिक तंत्र बन गया है। स्टार्ट अप पारिस्थितिक तंत्र में मेच्योर वर्टिकल (ई-वाणिज्य, एग्रीगेटर), उदीयमान वर्टिकल (वित्त-प्रौद्योगिकी, शिक्षा प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, आदि) और क्लाउड के आस-पास के इन्टरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), मशीन जानकारी, कृत्रिम आसूचना, रोबोटिक्स, 3डी मुद्रण के प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ, आदि की जरूरतें पूरा करने वाली फर्में सम्मिलित हैं। अमरीका आईटी-बीपीएम सेवाओं के लिए भारत का बड़ा बाजार है और इसके बाद यूके, यूरोप, (यूके को छोड़कर) और एशिया का स्थान है। ये हिस्से 2012-13 की अपेक्षा 2016-17 में बहुत नहीं बदल पाए हैं (चित्र 6)

चित्र 6. भारत का आईटी-बीपीएम निर्यात-क्षेत्रवार हिस्सा 2016-17(%)

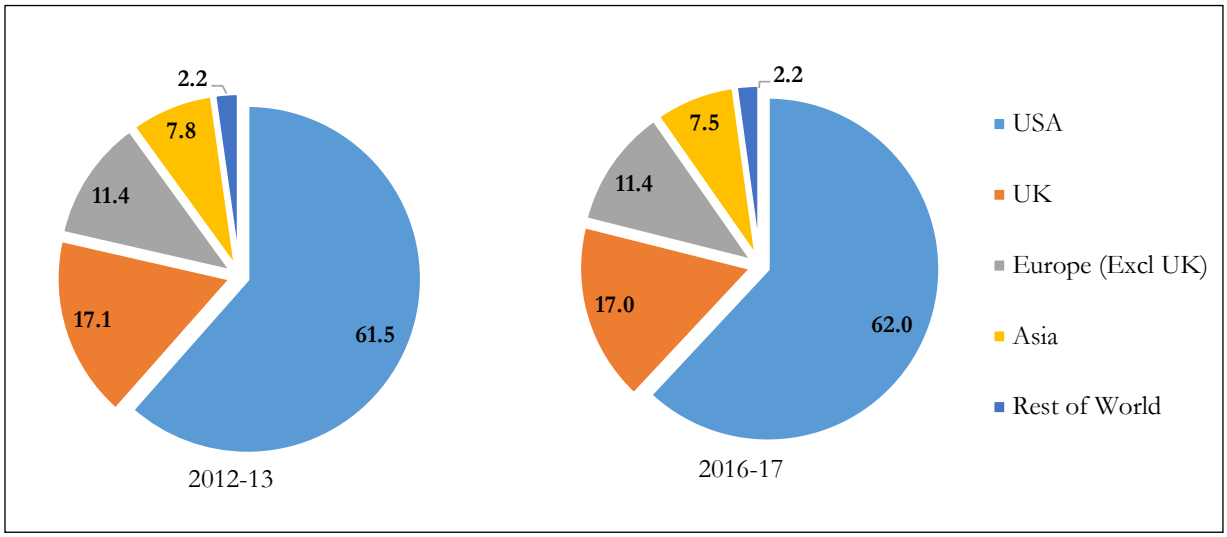

स्रोत: एनएएसएससीओएम।

9.34 नैसकाम के अनुसार, 2016-17 में हार्डवेयर सहित और रहित आईटी-बीपीएम क्षेत्र में भारत का कुल राजस्व (निर्यात+घरेलू) 7.8 प्रतिशत और 8.1 प्रतिशत की वृद्धियों के साथ क्रमश: 140 बिलियन अमरीकी डालर और 154 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंचने की संभावना है। हार्डवेयर सहित और रहित निर्यात दोनों 7.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए क्रमश: 117 बिलियन अमरीकी डालर और 116 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच सकते हैं। हार्डवेयर सहित और ई-कॉमर्स को छोड़कर घरेलू बाजार 8.5 प्रतिशत की दर पर बढ़कर 38 बिलियन अमरीकी डॉलर बिलियन तक पहुंचना तय है तथा हार्डवेयर और ई-कॉमर्स को छोड़कर(यह 10.4 प्रतिशत की दर पर बढ़कर 24 बिलियन अमरीकी डालर तक पहंचना तय है। यद्यपि आईटी सेवा क्षेत्र के केवल एक तिहाई परिमाण के साफ्टवेयर उत्पाद क्लाउड आधारित समाधानों, विशेषकर सर्वर मैसेज ब्लॉक (एसएमबी) के लिए सदा बढ़ती हुई मांग के कारण 10.4 प्रतिशत की वृद्धि पर 4.8 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंचने का अनुमान है। ई-वाणिज्य के 19.1 प्रतिशत की वृद्धि से 33 बिलियन तक पहुंचने की आशा है।

9.35 2002-03 से 2007-08 की अवधि में 27 से 38 प्रतिशत की ठोस वृद्धि पर मजबूती से बढ़ रहे भारत के सॉफ्टवेयर निर्यातों में गिरावट के कारण हालिया वर्षों में मंदी आ गई है। आर॰बी॰आई के बीओपी के आंकड़ों के अनुसार, 2016-17 में सॉफ्टवेयर निर्यात 2015-16 में 74.2 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 0.7 प्रतिशत की गिरावट के साथ 73.7 बिलियन अमरीकी डालर रह गया, जबकि नैसकाम के अनुसार आईटी-बीपीएम निर्यात 7.6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 117 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंचने की आशा है। नैसकाम द्वारा 2017-18 के लिए आईटी-बीपीएम की निर्यात-वृद्धि 7-8 प्रतिशत नियत की गई है (चित्र 7)।

9.36 भारत की कम्प्यूटर सेवाओं के निर्यातों में 2016 के दौरान 0.2 प्रतिशत की गिरावट (डब्ल्यूटीओ के आंकड़ों के अनुसार) तब भी हो रही है जब विश्व कम्प्यूटर सेवा का निर्यात 2016 में 5.8 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है और कुछ उन्नत, देशों जैसे अमरीका, इजरायल और दक्षिण-पूर्व एशिया लैटिन अमरीका और पूर्वी यूरोप के फिलीपीन्स, ब्राजील, चिली, रूस, यूक्रेन जैसे प्रतिस्पर्धाशील देशों, में वृद्धि सामान्य से काफी अधिक रही है (सारणी 10)। भारत के कम्प्यूटर-सेवा-आयात में भी 30.4 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है जिसके परिणामस्वरूप 2016 में (-) 1.7 प्रतिशत के ऋणात्मक निवल कम्प्यूटर सेवा-निर्यात हुए हैं। इससे जाहिर होता है कि आईटी-बीपीएम क्षेत्र न केवल वैश्विक मंदी और चुनौतीपूर्ण बाजार अभिगम स्थिति से वरन अन्य चुनौतियों से भी प्रभावित है (बॉक्स 2)।

चित्र 7. सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात और आईटी-बीपीएम राजस्व तथा निर्यात की वृद्धि

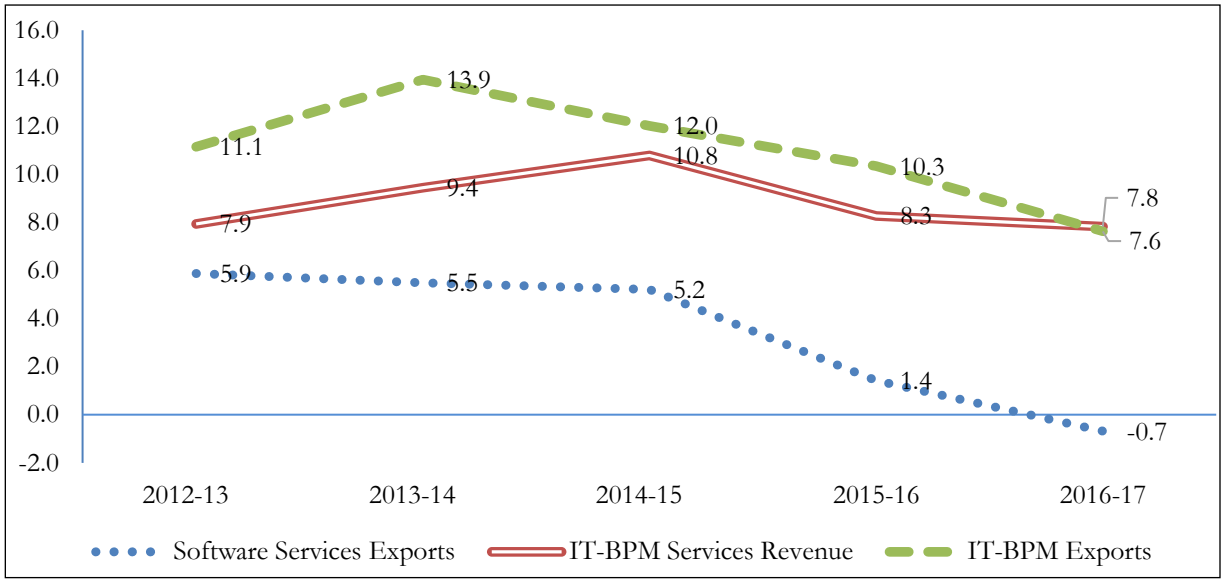

स्रोत: सॉफ्टवेयर सेवा: भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़े और आईटी-बीपीएम: नैसकॉम के आंकड़े।

सारणी 10. कम्प्यूटर सेवा निर्यात वृद्धि: चुनिंदा देश

	वृद्धि दर (%)				
	2009	2010	2014	2015	2016
आस्ट्रेलिया	-13.1	12.2	7.1	16.5	3.1
ब्राजील	6.5	-8.7	140.6	15.6	14.8
चिली	12.3	36.7	4.8	1.2	10.4
भारत	-9.0	20.5	1.3	1.2	-0.2
फिलीपिंस	35.3	24.1	10.1	1.3	63.6
रूस	-21.8	5.0	5.7	-7.4	8.5
यूक्रेन	9.5	24.7	16.1	11.2	18.4
यूएसए	3.8	1.9	7.4	12.7	8.1
इजराइल	1.3	-43.9	18.2	-2.0	26.9
विश्व	उ.न.	उ.न.	उ.न.	-3.6	5.8

स्रोत: विश्व व्यापार संगठन के आंकड़ों पर आधारित।

9.37 इसी बीच, भारत सरकार द्वारा सरकार से सरकार और सरकार से नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए एक प्लेटफार्म के रूप में प्रौद्योगिकियों को तेजी से अंगीकार किया जाना घरेलू आईटी-बीपीएम बाजार के लिए एक जबरदस्त उत्साहवर्धक कारक है। भारत सरकार डिजिटल प्रौद्योगिकियां अंगीकार करने में भी अग्रणी हो रही है और यह जनता के साथ संपर्क करने के साधनों के रूप में सामाजिक मीडिया के सर्वाधिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं में से एक है। इसने अपना स्वयं का धन प्लेटफार्म-मेघराज विकसित किया है जो सेवा के रूप में प्लेटफार्म (पास), सेवा के रूप में अवसंरचना (लास), सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर (सास) और सेवा के रूप में भंडारण (स्टास) की पेशकश करता है। इस पहल का केंद्र बिंदु सरकार के सूचना संचार एवं प्रौद्योगिकी (आईसीटी) व्यय को इष्टतम करते हुए देश में ई-सेवाओं की डिलीवरी की गति में तेजी लाना है। इसका इरादा भारत को विश्व के लिए साइबर सिक्योरिटी सोल्यूशन का एक प्रमुख केंद्र बनाना भी है। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटीज, ई-अभिशासन, कौशल भारत के माध्यम से डिजिटल प्रतिभा का संवर्धन,

बाक्स 2. आईटी-बीपीएमः मंदी की चुनौतियां

आईटी-बीपीएम उद्योग भी वैश्विक मंदी और वैश्विक राजनैतिक अनिश्चितताओं के दंश का अनुभव कर रहा है। क्योंकि इनसे ग्राहकों की अपने निर्णय लेने और निवेश की प्रक्रियाओं की गति मंद हो जाती है। प्रमुख बाजारों में भारत के आईटी-बीपीएम क्षेत्र द्वारा सामना की गई कुछ चुनौतियां इस प्रकार हैं।

बाजार तक पहुंचः एक आव्रजन मुद्दे के रूप में कुशल लोगों का गलत आवागमन इस वैश्विक कारोबार के विकास में एक बाधक है जिसके परिणामस्वरूप प्रमुख बाजारों में कौशल और आंकड़ों के मुक्त संचलन में अनेक बाधाएं आती हैं।

संयुक्त राज्य अमरीका में, ''अमरीकी खरीदो, अमरीकियों को काम पर लो'' जैसे राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेश के तहत आंकड़ों के संग्रहण, संवर्धित दूरदर्शिता और प्रवर्तन कार्रवाइयां, तथा उच्च कौशल वीजा कार्यक्रमों में सुधार लाने और कटौती करने के लिए प्रशासन संबंधी योजनाओं का विकास आवश्यक था। न्याय, मातृ भूमि सुरक्षा, राज्य और श्रम विभागों, सभी ने ज्ञापन, नीतिगत मार्गनिर्देश जारी कर दिए हैं जिनका उद्देश्य वीजा कार्यक्रमों पर नए प्रतिबंध लगाना, प्रवर्तन में संवृद्धि करना, प्रायोजकों की जांच-पड़ताल में वृद्धि करना, और उल्लंघनों के लिए शास्तियों में बढ़ोत्तरी करना है। यूएस सिटीजनशिप एंड इमीग्रेशन सर्विसेज ने एच-1बी वीजा के संबंध में एक नीतिगत ज्ञापन की शुरूआत की, जिसमें ''कम्पयूटर प्रोग्रामर्स'' विशेषज्ञता संबंधी व्यवसायों के रूप में स्वतः अर्हता प्राप्त नहीं करते है। सरकार की गहन विधीक्षा प्रक्रिया के भाग के रूप में डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट द्वारा वीजा आवेदकों से अतिरिक्त ब्यौरे अपेक्षित हैं। यह महत्वपूर्ण है कि श्रम विभाग की योजनाओं के अनुसार वर्तमान में कंपनियों को एच-1बी याचिकाएं प्रस्तुत करने से पूर्व लेबर कंडीशन अप्लीकेशन (एलएसी) से संबंधित और अधिक ब्यौरे प्रस्तुत करने चाहिए। एच-1बी वीजा से संबंधित विभिन्न बिल अमरीकी कांग्रेस में पटल पर रखे गए हैं, जिनमें से अद्यतन बिल सदन की न्यायपालिका समिति के अध्यक्ष बॉब गुडलेट्टे के दो बिल हैं जिन्हें तारीख 29 जून, 2017 को अमेरिकी कांग्रेस में पारित कर दिया गया है तथा अब उन्हें सीनेट में प्रस्तुत किया जा रहा है। इन दोनों बिलों में से एक बिल स्व-घोषित 'सैंक्चुअरि'' ऐसे नगरों को संघीय डालर नहीं प्रदान करेगा जो संघीय आव्रजन प्राधिकरणों से ऐसे निवासियों को संरक्षण देंगे, जबकि दूसरा बिल (जिसे केट्स लॉ भी कहा जाता है) अमरीका में अवैध रूप से पुनः प्रवेश करने वाले लोगों के लिए दंडों को सख्त करेगा।

यूके ने तारीख 06 अप्रैल, 2017 से प्रव्रजन सलाहकार समिति की सिफारिशें लागू कर दी हैं जिनमें श्रेणी-2 अंतः-कंपनी अंतरण (आईसीटी) अल्पावधिक वीजा मार्ग बंद करने, प्रति वैध वीजा वर्ष 1,000 पौंड प्रति प्रवासी का आव्रजन कौशल प्रभार (आई एस सी) और आव्रजन स्वास्थ्य प्रभार लगाना तथा श्रेणी-2 (आईसीटी) वीजा के लिए न्यूनतम वेतन की सीमा में बढ़ोतरी करना भी शामिल है। यूरोपीय संघ ने भी डाटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी रूल्स लागू किए हैं जो भारतीय कंपनियों को भारत से सेवाएं प्रदान करने पर कारगर ढंग से प्रतिबंध लगाते हैं, जबकि अमरीका को सुरक्षित आश्रय स्थल का दर्जा प्रदान किया गया है। आस्ट्रेलिया में, संघीय सरकार ने यह घोषणा की है कि यह वीजा की 457 श्रेणी को समाप्त करेगी और आस्ट्रेलियाई कामगारों के हितों की रक्षा करने के लिए इसके स्थान पर दो नई वीजा श्रेणियां लाएगी।

नव आगंतुकों से प्रतिस्पर्धाः भारतीय सेवा कंपनियों ने विगत दशक में आधुनिक अपतटीय उद्योग का सृजन करके विघटनकारी कंपनियों के रूप में अपनी ख्याति में सुधार किया था, किन्तु अब उनके स्थान को इस नए माहौल में उत्पन्न विशेषज्ञ और उपयुक्त स्टार्टअप के प्रबल समूह द्वारा चुनौती दी गई है। उपयुक्त कंपनियां ऐसे अत्यधिक विशेषज्ञतापूर्ण समाधानों का सृजन कर रही हैं जो उनके ग्राहकों की समस्याओं या मामलों का अतिविशिष्ट उपयोग द्वारा निराकरण करते हैं। ैसमेवितबमण्बवउ जैसे क्षैतिज या उद्यम प्लेटफार्म ऐसे संपूर्ण इकोसिस्टम का सृजन करते हैं जो अंतःप्रज्ञ घन-आधारित प्रौद्योगिकी के साथ समस्याओं का आसानी से समाधान करता है। भारत, ग्लोबैंट, ईपीएएम, और लक्सोफ्ट जैसी अपेक्षाकृत नई कंपनियों सहित पूर्वी यूरोप और लैटिन अमरीका से आगंतुकों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है।

रोजगार हानि की चुनौतियांः घन-आधारित सेवाओं जैसी डिजिटल प्रौद्योगिकियों में अपेक्षाकृत तीव्र गति से वृद्धि हो रही है और कंपनियों को नई प्रौद्योगिकियां और पुनः कौशल सीखना होता है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट (2016) के अनुसार, भारत में ऑटोमेशन से 69 प्रतिशत रोजगार खतरे में है, जबकि चीन में 77 प्रतिशत, इथोपिया में 85 प्रतिशत। एजीक्यूटिव सर्च फर्म हैड हंटर्स इंडिया के अनुसार, अपेक्षाकृत नवीन प्रौद्योगिकियों से तालमेल बिठाने में तैयारी पूरी न होने के कारण अगले तीन वर्षों के दौरान रोजगार में आईटी क्षेत्र में 1.75 लाख और 2 लाख के बीच वार्षिक कटौती होगी। मैक्किन्से एंड कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार आईटी सेवा कंपनियों में लगभग आधा कार्यबल अगले 3-4 वर्षों में ''अप्रासंगिक'' हो जाएगा तथा उद्योग के लिए भविष्य में 50-60 प्रतिशत कार्यबल को पुनःप्रशिक्षित करने की बड़ी चुनौती होगी क्योंकि प्रौद्योगिकियों में महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। आईटी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जबरी छुट्टी की भी रिपोर्टें हैं। हालांकि, नैसकॉम इसका विशेष रूप से खंडन करता है। नैसकॉम के अनुसार, निजी क्षेत्र के इस सबसे बड़े नियोजक ने विगत 3 वर्षों में 6 लाख से अधिक नए कर्मचारी जोड़े हैं और 2025 तक 2.5 से 3 मिलियन से अधिक रोजगार और जोड़ने की संभावना है। तथापि, कौशल की पृष्ठभूमि में तेजी से परिवर्तन किया जाना नियत किया गया है क्योंकि डिजिटल प्रौद्योगिकियों के इर्द-गिर्द कौशलों की मांग अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ती है। अनेक कंपनियों ने अपने मौजूदा कर्मचारियों को पुनः कौशल प्रदान करने के लिए समर्पित कार्यक्रमों की रचना की है। 2016-17 में, लगभग 1.7 लाख रोजगार सृजित किए गए और 2016-17 की चौथी तिमाही में ही शीर्ष 5 कंपनियों द्वारा 50,000 से अधिक कुल लोग काम पर लिए गए थे। किन्तु भारतीय श्रम ब्यूरो के आंकड़े यह इंगित करते हैं कि अप्रैल से दिसम्बर, 2016 के दौरान आईटी-बीओपी क्षेत्र में नियोजन में परिवर्तन केवल 0.22 लाख था। इस प्रकार भाड़े पर लेने वालों की निवल वृद्धि दर में मामूली कमी आई है जैसाकि नैसकॉम ने भी इंगित किया है।

घरेलू चुनौतियांः कुशल डिजिटल प्रतिभा की कमी, श्रेणी-2 और 3 के नगरों में अल्प-विकसित अवसंरचना और उत्पाद स्टार्टअप के लिए कुछ प्रतिबंधात्मक विनियमों जैसी कुछ घरेलू चुनौतियां भी हैं।

***स्रोतः* नैसकॉम एंड डेस्क रिसर्च से प्राप्त सूचना पर आधारित।**

नकदीरहित अर्थव्यवस्था के प्रति अभियान, स्टार्टअप इंडिया के जरिए अभिनवता लाने के प्रयास, आदि जैसी दीर्घावधि पहलों के माध्यम से भविष्य में प्रौद्योगिकी में स्थायी रूप से सुधार होने की आशा है।

भवन संपदा और आवासन

9.38 वर्ष 2015-16 में भारत की समग्र सकल मूल्य वृद्धि में स्वामित्व और निवास इकाइयों सहित भवन संपदा क्षेत्र का हिस्सा 7.6 प्रतिशत बैठता था। विगत 3 वर्षों में इस क्षेत्र की वृद्धि 2013-14 में 7.5 प्रतिशत से घटकर 2014-15 में 6.7 प्रतिशत तथा 2015-16 में और भी घटकर 4.5 प्रतिशत रह गई है। इसका मुख्य कारण समग्र सकल मूल्य वृद्धि में स्वामित्व और निवास इकाइयों का 6.8 प्रतिशत हिस्सा 2013-14 में 7.1 प्रतिशत से घटकर 2015-16 में 3.2 प्रतिशत रह जाना था। निर्माण क्षेत्र, जिसमें इमारतें, बांध, सड़कें, सेतु आदि शामिल हैं, की वृद्धि 2015-16 में 5.0 प्रतिशत से घटकर 2016-17 में 1.7 प्रतिशत रह गई है।

9.39 वर्ष 2016 में भारत के शीर्ष 8 नगरों में रिहायशी आवासों की बिक्री विगत 3 वर्षों में मांग में आई कमी के कारण पांच वर्ष के निम्नस्तर, लगभग 2,45,000 इकाइयां, रह गई है। इसी प्रकार, लांच की गई नई रिहायशी इकाइयों की बिक्री भी वर्ष 2016 के दौरान 1,76,000 इकाई रह गई है। लांच की गई इकाई में आई 64 प्रतिशत गिरावट महत्वपूर्ण थी जबकि बिक्री में लगभग एक-तिहाई की गिरावट आई। इसका मूल कारण दीर्घकालिक मंदी और परियोजना पूरा होने में विलंब रहा जिसके परिणामस्वरूप सभी नगरों में इन्वैंटरी बढ़ती गई। रोचक तथ्य यह है कि इस दीर्घकालिक मंदी के बीच भवन संपदा के प्रवर्तकों में एक सकारात्मक विकास (और अधिक परिपक्वता) ला रहा था और बाजार में नई आपूर्ति को सीमित कर रहा था, जिसके परिणामस्वरूप रिहायशी आवासों की बिक्री में 2015 और 2016 में लगातार दो वर्षों तक नई आपूर्ति की गति में कमी आई। नवम्बर, 2016 में हुए विमुद्रीकरण ने अल्पावधि में नवीन इकाइयों के लांच और बिक्री को संभवत: प्रभावित किया जिससे अनेक राज्यों में विमुद्रीकरण के पश्चात संपत्ति के पंजीकरण में गिरावट दर्ज की गई। निर्माण क्षेत्र के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) अंतर्वाह भी 2016-17 में 1.9 बिलियन अमरीकी डालर रह गया जबकि 2016-17 में यह 4.6 बिलियन अमरीकी डालर था, हालांकि गत दो से तीन वर्षों के दौरान निर्माण विकास क्षेत्र के लिए एफडीआई के मानदंडों में ढील दी गई थी। मांग में आई कमी के बावजूद, रिहायशी आवासों की कीमतों में एनएचबी रेजिडेक्स के साथ गिरावट नहीं आई, यह 2015-16 की चौथी तिमाही की तुलना में 2016-17 की चौथी तिमाही में 50 नगरों में से 33 नगरों में कीमतों में बढ़ोतरी दर्शाता है। वर्ष के दौरान सबसे अधिक बढ़ोतरी विशाखापत्तनम (24 प्रतिशत) में देखी गई इसके बाद रायपुर (16 प्रतिशत) का स्थान था (चित्र 8)। 2015-16 के औसत की अपेक्षा 2016-17 का रेजिडेक्स सूचकांक भी 50 नगरों में से 42 नगरों में हुई कीमत वृद्धि के साथ यही परिणाम दर्शाता है। 2016-17 की दूसरी तिमाही की तुलना में केवल 2016-17 की चौथी तिमाही (अर्थात् विमुद्रीकरण से पहली तिमाही) यह दर्शाती है कि 50 नगरों में से 32 नगरों में मकानों की कीमत में गिरावट आई है। लेकिन इसका कारण यह भी हो सकता है कि 50 नगरों में से क्रमश: 41 और 31 नगरों में पिछली तिमाहियों में मकानों की कीमतों में वृद्धि के साथ तिमाहियों की अपेक्षा 2016-17 की पहली और दूसरी दोनों तिमाहियों में मकानों की कीमतों में अचानक उछाल आया था।

9.40 भवन संपदा और आवासन क्षेत्र में वृद्धि को प्रभावित करने वाले कुछ मुद्दों और चुनौतियों में परमिटों का अनुमोदन, स्टाम्प ड्यूटी सहित उच्च भूमि पंजीकरण लागतें, ऋण स्तरों और अनर्जक आस्तियों का बढ़ना, कुशल कार्यबल का अभाव तथा भवन निर्माताओं द्वारा मकानों का विलंब से दिया जाना शामिल हैं। वर्ल्ड बैंक की 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2017' के अनुसार, निर्माण परमिटों पर कार्रवाई करने वाले 190 देशों में से भारत का स्थान 185वां है। भारत में किसी भवन संपदा परियोजना को विकसित करने के लिए किसी प्रवर्तक द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अपेक्षित 30-35 विनियामकों के अनुमोदनों होते हैं फिर भी विभिन्न अनुमोदनों के लिए छह से बारह महीने या इससे भी अधिक समय लग जाता है। इसके परिणामस्वरूप, संपूर्ण प्रक्रिया बोझिल हो जाती है और इससे विलंब भी होता है। इसके चलते परियोजना की लागत 20-30 प्रतिशत बढ़ जाती है।

चित्र 8. आवासन मूल्य चुनौतियां (2015-16 तिमाही 4 के मुकाबले 2016-17 तिमाही 4)

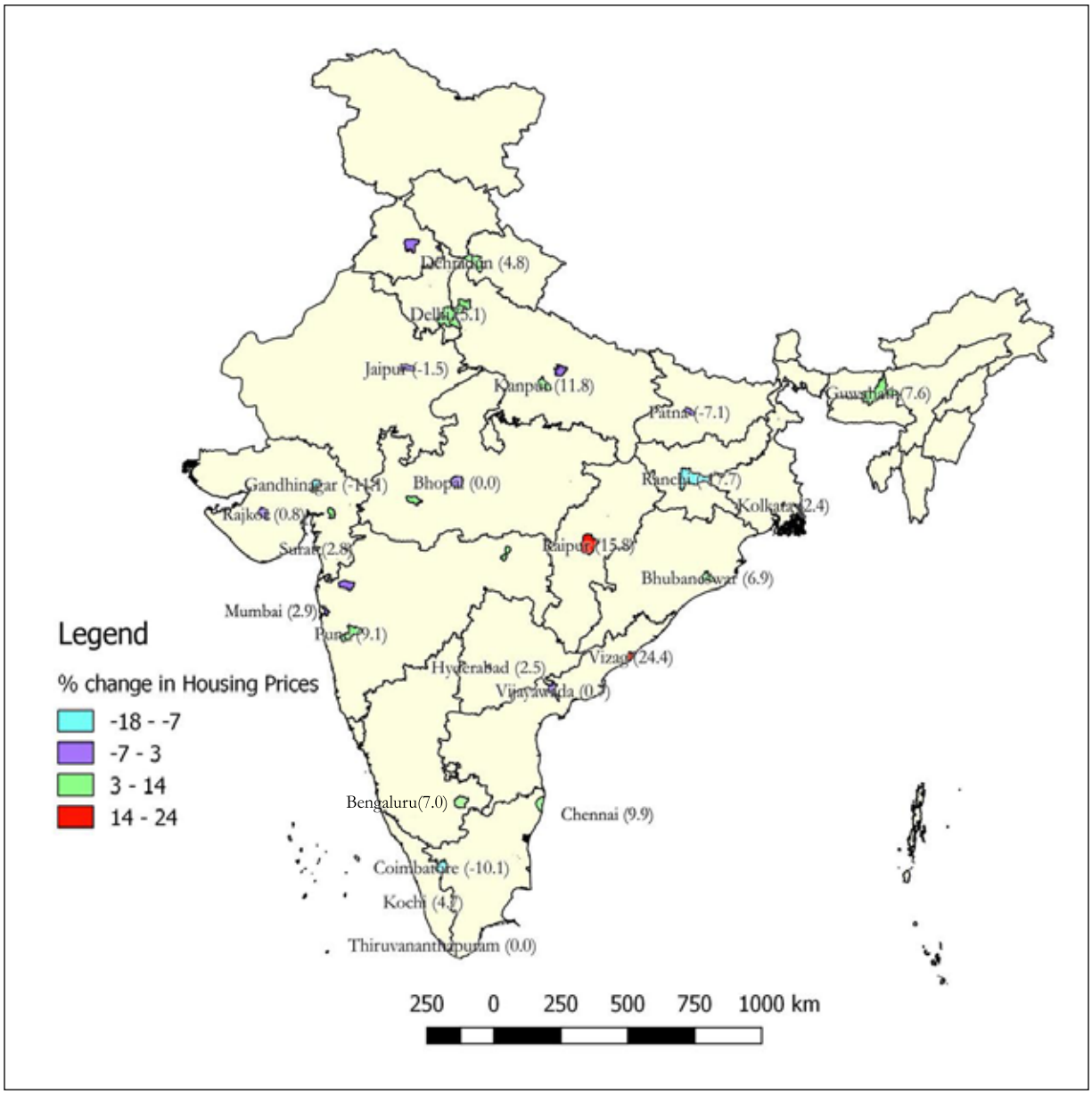

स्रोत: **एनएचबी रेजिडेक्स इंडेक्स डाटा पर आधारित।**

संपत्ति को रजिस्टर करने वाले 190 देशों में से भारत का स्थान 138वां है। उप-नियम भी वैश्विक बेंचमार्क और सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुसार अद्यतन नहीं किए गए हैं। अनर्जक आस्तियों (एनपीए) का बढ़ना, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भवन संपदा क्षेत्र को निर्दिष्ट उच्चतर जोखिमकारी उपबंध तथा भवन संपदा क्षेत्र में लाभों का कम होते जाना जैसे कारकों के चलते बैंकों द्वारा इस क्षेत्र को उधार देने पर असर पड़ता है। भवन संपदा क्षेत्र को उधार देने वाले बैंकों में 2010 में 57 प्रतिशत से 2016 में 24 प्रतिशत से भी कम की उल्लेखनीय गिरावट आई है, जबकि निजी इक्विटी निवेश में वृद्धि हुई है (एनएआरईडीसीओ और केपीएमजी) 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की कुल आवासन ऋण बकाया राशि 15.2 प्रतिशत की वृद्धि (वर्षानुवर्ष) के साथ लगभग 8.6 ट्रिलियन रुपए थी जबकि आवासन वित्त कंपनियों (एचएफसी) की कुल आवासन ऋण बकाया राशि इसी अवधि के दौरान 15.0 प्रतिशत की वृद्धि के साथ

5.0 ट्रिलियन रुपए थी। भवन संपदा क्षेत्र नकदी की समस्याओं और बढ़ते जा रहे ऋण से भी जूझ रहा है। भारत में सूचीबद्ध भवन संपदा प्रवर्तकों का कुल बकाया ऋण 2006-07 में 25,000 करोड़ रुपए (3.7 बिलियन अमरीकी डालर) से बढ़कर 2015-16 में 83,000 करोड़ रुपए (12 बिलियन अमरीकी डालर) हो गया है (एनएआरईडीसीओ और केपीएमजी)।

9.41 सरकार ने भवन संपदा और आवासन क्षेत्र की सहायता करने के लिए अनेक नीतियां तैयार की हैं। सरकार द्वारा किए गए कुछ हालिया नीतिगत उपायों में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई-शहरी), भवन संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016, स्मार्ट सिटीज मिशन, भवन संपदा निवेश न्यास (आरईआईटी) और अवसंरचना निवेश न्यास (इन्व आईटी), सस्ती आवासन परियोजनाओं के लिए कर-प्रोत्साहक दावा करने के लिए शर्तों में छूट, और बेनामी लेन-देन (प्रतिषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 शामिल हैं।

उपग्रह-मानचित्रण और प्रक्षेपण सेवाएं

9.42 भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, जिसमें सामाजिक विकास और कार्यनीतिक अपेक्षाओं से संबंधित मुद्दों का निराकरण करने के लिए संचार, नौसंचालन तथा भू-प्रक्षेपण शामिल हैं, की अनुप्रयोज्यता के जरिए राष्ट्रीय विकास में योगदान देता है। पिछले तीन दशकों से, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष और लिए गए आदानों को समाविष्ट करते हुए मिश्रित मॉडलों के विकास, निर्णय में सहायता और शीघ्र चेतावनी प्रणालियों के विकास के लिए आसान मानचित्रण अनुप्रयोज्यताएं उपलब्ध कराने से परिपक्व हो गई है। अनेक बार अंतरिक्ष संबंधी अनुप्रयोज्यता के लाभ अमूर्त प्रकृति के होते हैं और उनकी मात्रा का निर्धारण नहीं किया जा सकता। तथापि, कुछ मामलों में कतिपय अंतरिक्ष अनुप्रयोज्यताओं के आर्थिक लाभों की मात्रा निर्धारित की जा सकती है जो उन प्रयोज्यताओं से इसके सामाजिक आयाम के अनुरूप महत्वपूर्ण योगदान को इंगित करते हैं। उपग्रह-मानचित्रण और प्रक्षेपण सेवाएं दो ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें भारत अपनी छाप छोड़ रहा है और भविष्य में इसकी बृहत संभावना है।

उपग्रह मानचित्रण

9.43 विगत दशकों से, भू-प्रेक्षण (ईओ) आंकड़े, यथा स्थान प्रेक्षण और यंत्रों के साथ एकीकृत, भू और जल, महासागर और वातावरण, पर्यावरण और ईको प्रणाली, शहरी और ग्रामीण अनुप्रयोज्यताओं तथा आपदा जोखिम में कमी के क्षेत्रों में अनुप्रयोज्यताओं की मेजबानी में सहायता करते रहे हैं। अंतरिक्ष संबंधी कुछ अनुप्रयोज्यताओं और सेवाओं से राजस्व का सृजन होता है और भारत के लिए विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है। इनमें आईआरएस उपग्रहों से सीधे आंकड़े प्राप्त करने और उन्हें संसाधित करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रदान करके अंतर्राष्ट्रीय सतही केंद्रों (आईजीएस) की स्थापना, जब उपग्रह अपने सतही केंद्र से गुजर जाते हैं; उनके सतही केंद्र में वास्तविक आंकड़ा अर्जन पर आधारित पहुंच शुल्क; इन आईजीएस द्वारा अपने ग्राहकों को अनुज्ञप्त आंकड़ों के लिए रॉयल्टी; विकासशील देशों को सीधे ही या अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को पुन: विक्रेताओं के माध्यम से आईआरएस उपग्रह आंकड़ा उत्पादों की लाइसेंसिंग, आदि शामिल हैं।

9.44 विगत तीन वर्षों में भारत द्वारा उपग्रह मानचित्रण से अर्जित विदेशी मुद्रा की राशि 100 करोड़ रुपए से अधिक थी। इसमें से, सर्वाधिक अर्जन जर्मनी (57.4 प्रतिशत) से प्राप्त हुआ था, इसके बाद अल्जीरिया (12.5 प्रतिशत) और चीन (6.5 प्रतिशत) का स्थान था। तथापि, हालिया वर्षों में विदेशी मुद्रा अर्जनों में कमी आई है (सारणी 11)। 2014-15 से, चीन और म्यांमार, जो भारत के चार शीर्ष बाजारों में थे, ने इन सेवाओं का उपयोग करना बंद कर दिया है। चीन के मामले में, करार समाप्त हो गए और चीन ने एक भाग या अपने भू-प्रेक्षण कार्यक्रम के रूप में ऑप्टिकल और माइक्रोवेव में उपग्रहों की श्रृंखला विकसित की है जो स्थानिक और स्पेक्ट्रल के विविध प्रकार के आंकड़े उपलब्ध करा रहे हैं। म्यांमार के मामले में, एंट्रिक्स-अंतरिक्ष विभाग की वितरण इकाई, नए सिरे से सहयोग करने का प्रयास कर रही है। इसके अतिरिक्त, इसरो भारतीय रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट्स (रिसोर्ससेट-2 और ओशियनसेट-2 से) आंकड़े प्राप्त करने और उन्हें संसाधित करने के लिए म्यांमार सहित आसियान सदस्यों को सहायता प्रदान करने और आसियान सदस्य देशों के लाभार्थ अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोज्यताओं में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भी एक परियोजना का अनुगमन कर रहा है।

सारणी 11. सेटेलाइट मैपिंग सेवा निर्यात (आईआरएस संबंधी सेवा)

विदेशी मुद्रा अर्जित (करोड़ रुपए में)						
	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	संचयी
कुल	38.09	14.82	28.84	25.10	11.38	118.23
जर्मनी	20.86	9.88	11.52	17.97	7.57	67.80
अल्जिरिया	2.80	0.70	8.96	2.38	--	14.84
चीन	6.74	0.87	0.11	--	--	7.72
म्यंमार	2.64	2.16	2.40	--	--	7.20
ईरान	--	--	0.88	3.52	2.48	6.88
नार्वे	--	--	4.15	1.23	0.63	6.01
फ्रांस	2.19	1.17	--	--	--	3.36
यूएसए	2.80	--	--	--	--	2.80
यूके	--	--	0.82	--	0.70	1.52

***स्रोतः* एंट्रिक्स, इसरो।**

9.45 भू-स्थानिक बाजार में मूल रूप से आंकड़ा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और मानचित्रण सहित सेवाएं शामिल हैं। उपर्युक्त में से, आंकड़ा संघटक केवल 5 प्रतिशत है। इस आंकड़ा संघटक में से, एशिया प्रशांत क्षेत्र का योगदान 14 प्रतिशत है। अनेक उच्च समाधान आंकड़ा प्रदाताओं के कारण बाजार में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा है। एंट्रिक्स, अब केवल मध्यम और अपरिष्कृत समाधान आंकड़ा उत्पादों का विपणन करने में समर्थ है। अनेक देशों में मुफ्त और मुक्त आंकड़ा नीति, खासकर अमेरिका के लैंड सेट-8, और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) से मुफ्त आंकड़ों की उपलब्धता जिसके परिणामस्वरूप ये आंकड़े पूरे विश्व को व्यावहारिक रूप से मुफ्त मिल रहे हैं, के कारण मध्यम और अपरिष्कृत समाधान आंकड़ा खंड के लिए वाणिज्यिक संभावना गंभीर चुनौती का सामना कर रही है। फिलहाल अनेक देश दूर संवेदी आंकड़ों को सामाजिक या सार्वजनिक वस्तु के रूप में मान रहे हैं। चालू परिदृश्य में केवल उच्च और अति-उच्च समाधान आंकड़ों के ही वाणिज्यिक बाजार हैं। इस बाजार में भी विश्व भर में अनेक निजी उपग्रह प्रचालकों की वजह से अत्यधिक प्रतिस्पर्धा है। फिलहाल, एंट्रिक्स, पूरे विश्व में विभिन्न उपयोगकर्ताओं को कार्टोसेट-1 डाटा (जो 2.5 एम स्टीरियो डाटा की पेशकश करता है) का विपणन कर रहा है और इस डाटा खंड में एंट्रिक्स का योगदान मामूली (0.5 प्रतिशत से कम) है। तथापि, उच्च/अति-उच्च समाधान डाटा उपग्रहों के कार्यान्वयन के साथ इस स्थिति में सुधार होने की संभावना है।

उपग्रह प्रक्षेपण

9.46 भारत ने पृथ्वी की कक्षा में स्वदेशी उपग्रहों का आत्मनिर्भर तरीके से अपना प्रक्षेपण यान विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया। भारत का प्रचालनात्मक कार्योपयोगी यान, पोलर सेटेलाइट लांच व्हीकल (पीएसएलवी) एक चार-स्टेज वाला यान है जिसे ध्रुवीय सूर्य-समकालिक कक्षा में दूर संवेदी उपग्रहों को ले जाने के लिए तैयार किया गया है। 10 जुलाई, 2017 की स्थिति के अनुसार, पीएसएलवी के 40 प्रक्षेपण किए जा चुके हैं। पिछली बार संचालित 39 मिशनों ने सफलताओं की झड़ी लगा दी है, यद्यपि ध्रुवीय कक्षाओं में दूर संवेदी उपग्रहों के प्रक्षेपण हेतु प्रारंभिक रूप में निर्मित यान संचार, मौसम विज्ञान और नौचालन उपग्रहों को उप-भू अंतरण कक्षा (सब-जीटीओ) में प्रक्षेपित करने के अनुरूप रहा है। स्वदेशी रूप से निर्मित उपग्रहों के प्रक्षेपण के अलावा, पीएसएलवी एंट्रिक्स के साथ वाणिज्यिक व्यवस्थाओं के जरिए ग्राहकों को उपग्रह प्रक्षेपण सेवाएं भी प्रदान करता है। मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, पीएसएलवी ने 225 उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिए हैं। इनमें

सारणी 12. सेटेलाइट प्रक्षेपण सेवा निर्यात

वित्त वर्ष	विदेशी मुद्रा अर्जन (करोड़ में रुपए)*	सेटेलाइट प्रक्षेपण सेवा का प्रयोग करने वाले देश	वैश्विक सेटेलाइट प्रक्षेपण सेवा राजस्व (यूरो मिलियन)	वैश्विक सेटेलाइट प्रक्षेपण सेवा राजस्व में भारत का हिस्सा (प्रतिशत)
2012-13	136.18	कनाडा, फ्रांस, जापान, यूके	5160	0.4
2013-14	--	--	4800	--
2014-15	149.41	कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर	5250	0.3
2015-16	394.22	कनाडा, इंडोनेशिया, सिंगापुर, यूके, यूएसए	4800	1.1
2016-17	274.66	अल्जिरिया, कनाडा, जर्मनी, इंडोनेशिया, नीदरलैंड, यूएसए	लागू नहीं	--

स्रोत: **इसरो ''सेटेलाइट इंडस्ट्री एसोसिएशन'' द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रकाशित ''स्टेट ऑफ दा सेटेलाइट इंडस्ट्री रिपोर्ट'' पर आधारित।**

टिप्पणी: *अर्जन प्रक्षेपण के वर्ष में दर्ज किए गए हैं।

37 राष्ट्रीय उपग्रह, विश्वविद्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों द्वारा निर्मित 8 विद्यार्थी उपग्रह, एक पुनः-प्रविष्टि मिशन और 23 देशों के 180 विदेशी उपग्रह शामिल हैं।

9.47 अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह ग्राहकों को प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के लिए, एंट्रिक्स ग्राहक और इसरो के बीच एकल नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है और ग्राहक को शुरू से अंत तक सहयोग प्रदान करता है। उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं के निर्यात से भारत के विदेशी मुद्रा अर्जन में 2015-16 और 2016-17 में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और इसके परिणामस्वरूप वैश्विक उपग्रह प्रक्षेपण सेवा राजस्व में भारत के हिस्से में भी बढ़ोतरी हुई है (सारणी 12)। 2015-16 में विदेशी मुद्रा अर्जन 2016-17 की तुलना में अधिक था क्योंकि 2015-16 में अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए समर्पित ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी) मिशनों की संख्या दो थी, जबकि 2016-17 में भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह मिशनों के लिए सह-यात्रियों के रूप में केवल अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था।

9.48 पीएसएलवी और भू-समकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान (जीएसएलवी) के सफल कीर्तिमान तथा वैश्विक रूप से लघु उपग्रह बाजार के उभरने, (खासकर अमरीका और यूरोप में), के साथ, एंट्रिक्स को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा अपनी निचली पृथ्वी कक्षा (एलईओ) उपग्रहों, जिनमें समर्पित प्रक्षेपण विकल्प के रूप में पीएसएलवी के बोर्ड पर तारामंडल नक्षत्रों और जीएसएलवी के बोर्ड पर अपेक्षाकृत छोटे संचार उपग्रह शामिल हैं, के प्रक्षेपण के लिए पीएसएलवी और जीएसएलवी प्रक्षेपण सेवाओं के काफी अधिक उपयोग की संभावनाएं दिखाई देती हैं।

निष्कर्ष

9.49 भारत की सेवा क्षेत्र वृद्धि, जो वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान भी अत्यधिक क्षमतापूर्ण थी, उसमें हालिया समय में नरमी दिखाई दे रही है। तथापि, हालिया महीनों में बेहतर निष्पादन दर्शाने वाले क्षेत्र के कुछ खंडों में सुधार दिखाई देता है। यह निक्केई सर्विसेज़ पीएमआई ऑफ इंडिया में भी प्रतिबिम्बित होती है, जो नए कारोबार के अंतर्वाहों में ठोस और अपेक्षाकृत अधिक मजबूत उछाल के समर्थन से जून, 2017 में बढ़कर 53.1 हो गई। यह अक्तूबर, 2016 से सर्वाधिक मजबूत है।